



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082024-256512  
CG-DL-E-21082024-256512

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 210]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 14, 2024/श्रावण 23, 1946

No. 210]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 14, 2024/SHRAVANA 23, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम निष्कर्ष

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2024

मामला संख्या एडी(ओआई) – 09/2023

विषय: चीन जन गण में उत्पन्न या निर्यात किए गए "आइसोप्रोपिल अल्कोहल" के आयात से संबंधित पाटन रोधी जांच।

फ. सं. 6/09/2023-डीजीटीआर:- समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (डंप की गई वस्तुओं पर पाटन रोधीशुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह और क्षति के निर्धारण के लिए) नियम, 1995, (इसके बाद 'एडी नियम' या 'पाटन रोधीनियम' या 'नियम' के रूप में संदर्भित);

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इसके बाद "आवेदक" के रूप में भी संदर्भित) ने समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमा शुल्क टैरिफ (डंप की गई वस्तुओं पर पाटन रोधीशुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह और क्षति के निर्धारण के लिए) नियमों के अनुसार नामित प्राधिकारी (इसके बाद "प्राधिकरण" के रूप में भी संदर्भित) के समक्ष एक आवेदन दायर किया, चीन जनगण (जिसे इसके बाद "विषय देश" भी कहा गया है) में उद्भूत या उससे निर्यातित आइसोप्रोपिल अल्कोहल (जिसे

इसके बाद विचाराधीन उत्पाद या विषय माल या आईपीए भी कहा गया है) के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए समय-समय पर यथा संशोधित (इसके बाद "नियम" या "पाटनरोधी नियम" के रूप में संदर्भित) समय-समय पर यथा संशोधित (इसके बाद "नियम" या "पाटनरोधी नियम" के रूप में संदर्भित) के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए 1995 के प्रावधानों को लागू किया गया है।

2. प्राधिकरण ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, अधिसूचना संख्या 6/09/2023-डीजीटीआर दिनांक 29 सितंबर 2023 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित असाधारण है, ने संबंधित वस्तुओं के कथित डंपिंग के अस्तित्व, डिग्री और प्रभाव को निर्धारित करने के लिए नियमों के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9ए के अनुसार विषय जांच शुरू की, (ग) संबंधित देश में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने के लिए जो यदि उद्ग्रहण की जाती है तो घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

#### ख. प्रक्रिया

3. नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन विषय जांच के संबंध में किया गया है:

- क. प्राधिकरण ने नियम 5 सुप्रा के उप-नियम (5) के अनुसार जांच शुरू करने के लिए आगे बढ़ने से पहले वर्तमान पाटन रोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबंधित देश के दूतावास को अधिसूचित किया।
- ख. प्राधिकरण ने 29 सितंबर 2023 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया, जिसमें संबंधित देश से संबंधित वस्तुओं के आयात के संबंध में पाटन रोधी जांच शुरू की गई।
- ग. प्राधिकरण ने प्रश्नावली के साथ दीक्षा अधिसूचना की एक प्रति भारत में संबंधित देश के दूतावास, संबंधित देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग के साथ-साथ अन्य घरेलू उत्पादकों को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-मेल पत्तों के अनुसार भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे अपने विचारों से अवगत कराएं। लिखित रूप में, निर्धारित समय सीमा के भीतर।
- घ. प्राधिकरण ने नियमों के नियम 6(3) के अनुसार आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण की एक प्रति भारत में संबंधित देश के दूतावास, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, आयातकों और उपयोगकर्ताओं को प्रदान की।
- ङ. भारत में संबंधित देश के दूतावास से भी अनुरोध किया गया था कि वह अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावली का उत्तर निर्धारित समय-सीमा के भीतर देने की सलाह दे। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी उन्हें संबंधित देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पते के साथ भेजी गई थी।
- च. प्राधिकरण ने नियमों के नियम 6(4) के अनुसार विषय देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी:
  1. अवंतोर प्रदर्शन सामग्री
  2. चांग चुन केमिकल (पंजिन)
  3. डेझोउ डेटियन केमिकल
  4. हुबेई केलिन बोलुन न्यूमैटेरियल्स कंपनी
  5. मित्सुई केमिकल्स
  6. पेट्रोचाइना जिनझोउ पीसी
  7. शेडोंग दादी सुपू केमिकल
  8. यानचेंग सुपर केमिकल टेक्रोलॉजी
  9. झेजियांग सिन्हुआ केमिकल कंपनी लिमिटेड
  10. जिबो नाल्कोहॉल केमिकल कंपनी
  11. हाई-टेक स्प्रिंग केमिकल कंपनी

12. झुहाई लॉन्ग सक्सेस केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
- छ. निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्राधिकरण द्वारा जारी निर्यातकों की प्रश्नावली का जवाब दायर किया।
1. झुहाई लॉन्ग सक्सेस केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
  2. फॉक्स केम पीटीई लिमिटेड
  3. एसके केमिकल ट्रेडिंग (एचके) लिमिटेड
- ज. प्राधिकरण ने भारत में विषयगत वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजी जिसमें नियमों के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगी गई है:
1. अदामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
  2. अमी रिद्धि केम प्राइवेट लिमिटेड
  3. आर्कोमा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
  4. अर्केमा पेरोक्साइड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
  5. एस्पेन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
  6. ऑरिगेन डिस्कवरी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
  7. अरबिंदो फार्मा लिमिटेड
  8. भारत ज्योति इम्पेक्स
  9. बायोकॉन लिमिटेड
  10. ब्रेनटैग इंग्रीडिएंट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
  11. सी जे शाह एंड सीओ
  12. केमीटेक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
  13. केमिकल कॉर्प प्राइवेट लिमिटेड
  14. फ्लोरा केमिकल्स
  15. हेज़ल मर्केटाइल लिमिटेड
  16. इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड
  17. के. उत्तमलाल एंड एरो; कंपनी
  18. खुशबू दाई केम प्राइवेट लिमिटेड
  19. केएलजे रिसोर्सेज लिमिटेड
  20. एल जे इंटरनेशनल लिमिटेड
  21. लॉरस लैब्स लिमिटेड
  22. लोक केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
  23. ल्यूपिन लिमिटेड
  24. महाराष्ट्र केमिकल प्रोडक्ट्स
  25. मयूर केमिकल्स
  26. माइक्रो लैब्स लिमिटेड
  27. माइलैन लैबोरेटरीज लिमिटेड

28. निकॉन कॉर्पोरेशन
  29. ओवरसीज पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
  30. आर.आर. इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड
  31. रिलायंस ऑर्गेनिक
  32. संजय केमिकल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
  33. सम्मान ट्रेड इम्पेक्स
  34. सराका लेबोरेटरीज लिमिटेड
  35. सत्या दीप्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
  36. श्री बांके बिहारी लाल बोर्ड मिल्स
  37. सिग्रेट केमिकल कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
  38. सिमराइज प्राइवेट लिमिटेड
  39. टी.एम. ठाकोर फार्मास्युटिकल लैबोरेट्रीज
  40. टेक्नोवाइमेजिंगसिस्टम्सप्राइवेटलिमिटेड
  41. टेवा एपीआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
  42. ट्राइडेंटचेम्फरलिमिटेड
  43. उर्मी केमिकल्स
  44. वी.डी.एच. ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
  45. वर्टेक्स केमिकल्स
  46. विविमेडलैब्सलिमिटेड
  47. याशो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
  48. जेडसीएल केमिकल्स लिमिटेड
  49. रमणीकलाल
  50. पायनियर केमिकल्स
  51. शिवटेक्स
  52. उज्जिनफार्मा
  53. बृहस्पति भगवान रसायन
  54. पोन प्योर केमिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- झ. किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने प्राधिकरण द्वारा जारी आयातकों/प्रयोक्ताओं की प्रश्नावली का उत्तर दाखिल करके वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है।
- ज. प्राधिकरण ने सभी इच्छुक पार्टियों और संबंधित मंत्रालय को आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की। निम्नलिखित पार्टियों ने आर्थिक हित प्रश्नावली का जवाब दायर किया है।
1. घरेलू उद्योग
  2. झुहाई लॉन्ग सक्सेस केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
- ट. गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में इच्छुक पक्षों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई जानकारी की जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकरण ने गोपनीयता के दावों को, जहां कहीं

आवश्यक था, स्वीकार कर लिया है और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है और अन्य इच्छुक पार्टियों को खुलासा नहीं किया गया है। जहां कहीं संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त गैर-गोपनीय विवरण उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

- ठ. इच्छुक पार्टियों को 21 फरवरी 2024 की अधिसूचना के माध्यम से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रियाओं, प्रस्तुतियों और सबूतों के गैर-गोपनीय संस्करण को अन्य इच्छुक पार्टियों के साथ साझा करने के लिए कहा गया था।
- ड. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से अनुरोध किया गया था कि वे पिछले तीन वर्षों के लिए संबंधित वस्तुओं के आयातों का लेन-देन-वार ब्यौरा और जांच की अवधि, जो प्राधिकरण को विधिवत प्राप्त हुई थी, उपलब्ध कराई जाए। प्राधिकरण ने आयात की मात्रा की गणना के उद्देश्य से डीजी सिस्टम डेटा पर भरोसा किया है।
- ढ. गैर-हानिकारक मूल्य (एनआईपी) का निर्धारण उत्पादन की लागत और भारत में संबंधित वस्तुओं को बनाने और बेचने की लागत के आधार पर किया गया है, जो घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार रखा गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वर्तमान अंतरिम पाटन रोधीशुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।
- ण. वर्तमान पाटन रोधीजांच के उद्देश्य से जांच की अवधि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 (12 महीने) तक है। क्षति की जांच अवधि को 1 अप्रैल 2019 - 31 मार्च 2020, 1 अप्रैल 2020 - 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022 और जांच की अवधि की अवधि के रूप में माना गया है।
- त. प्राधिकरण ने अन्य इच्छुक पाटनों से आवश्यक सीमा तक और सूचना मांगी। अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रदान किए गए डेटा का सत्यापन वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए आवश्यक समझी जाने वाली सीमा तक आयोजित किया गया था। प्राधिकरण ने वर्तमान मामले में अपने विश्लेषण में इच्छुक पार्टियों के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।
- थ. नियमों के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकरण ने इच्छुक पक्षों को 26 जून, 2024 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षों से मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों की लिखित प्रस्तुतियाँ दर्ज करने का अनुरोध किया गया था, इसके बाद प्रत्युत्तर प्रस्तुतियाँ दी गईं।
- द. इच्छुक पक्षों द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, उठाए गए तर्क और जांच के दौरान विभिन्न इच्छुक पक्षों द्वारा प्रदान की गई जानकारी, जिस हद तक साक्ष्य के साथ समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक माने जाते हैं, वर्तमान अंतिम निष्कर्षों में प्राधिकरण द्वारा उचित रूप से विचार किया गया है।
- ध. प्राधिकरण ने जांच के दौरान इच्छुक पक्षों द्वारा दी गई सूचना की सटीकता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट किया जो संभव सीमा तक वर्तमान अंतिम निष्कर्षों का आधार बनता है और प्रासंगिक, व्यवहार्य और आवश्यक समझी जाने वाली सीमा तक घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/दस्तावेजों का सत्यापन किया।
- न. गोपनीयता दावों की पर्याप्तता के संबंध में इच्छुक पक्षों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई जानकारी की जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकरण ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है, जहां भी आवश्यक है, और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है और अन्य इच्छुक पार्टियों को खुलासा नहीं किया गया है। जहां कहीं संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त गैर-गोपनीय विवरण उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- त. जहां कहीं भी किसी इच्छुक पक्ष ने जांच के दौरान पहुंच से इनकार कर दिया है, या अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की है, या जांच में काफी बाधा डाली है, प्राधिकरण ने ऐसे इच्छुक पक्षों को गैर-सहयोगी माना और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वर्तमान अंतिम निष्कर्ष दर्ज किए।

- प. वर्तमान अंतिम निष्कर्ष में '\*\*\*\*' गोपनीय आधार पर एक इच्छुक पार्टी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी का प्रतिनिधित्व करता है, और इसलिए नियमों के तहत प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाता है।
- फ. विषय जांच के लिए प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1USD = ₹ 81.06 है

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

- ग.1 अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तुतियाँ
4. विचाराधीन या लेख की तरह उत्पाद के दायरे के संबंध में अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा कोई प्रस्तुतियाँ नहीं की गई हैं।
- ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ
5. विचाराधीन उत्पाद के दायरे और इसी तरह के लेख के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण इस प्रकार हैं:
- विचाराधीन उत्पाद आइसोप्रोपिल अल्कोहल (आईपीए) है जिसे आइसोप्रोपेनाॅल भी कहा जाता है।
  - आईपीए या तो कच्चे माल के रूप में प्रोपलीन या एसीटोन का उपयोग करके निर्मित किया जा सकता है।
  - आईपीए एक मजबूत गंध के साथ एक रंगहीन, ज्वलनशील तरल है और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के औद्योगिक और घरेलू रसायनों के निर्माण के लिए किया जाता है। आईपीए का उपयोग थोक दवाओं और दवा फॉर्मूलेशन के उत्पादन में प्रमुख अनुप्रयोगों के लिए भी किया जाता है जो दवा निर्माण में महत्वपूर्ण हैं।
  - इसका उपयोग एंटीसेप्टिक्स, कीटाणुनाशक और डिटर्जेंट जैसे रसायनों में एक सामान्य घटक के रूप में भी किया जाता है।
  - विचाराधीन उत्पाद में 99.8% आईपीए, 0.1% पानी और अवशिष्ट अशुद्धियाँ शामिल हैं।
  - घरेलू उद्योग द्वारा विनिमत उत्पाद वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से प्रतिस्थापन योग्य है और उपभोक्ताओं द्वारा एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जा रहा है। अतः घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबंधित देश से आयातित वस्तु के समान होता है।

ग.3 प्राधिकरण की जांच

6. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद आइसोप्रोपिल अल्कोहल या आईपीए है। आईपीए को आइसोप्रोपेनाॅल के रूप में भी जाना जाता है और यह रासायनिक सूत्र  $CH_3CHOHCH_3$  वाला एक यौगिक है।
7. आईपीए का उत्पादन या तो एसीटोन मार्ग या प्रोपलीन मार्ग का उपयोग करके किया जा सकता है। आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि वे आईपीए के निर्माण के लिए प्रोपलीन मार्ग का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि, इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि दो अलग-अलग मार्गों के माध्यम से आईपीए का उत्पादन, जिसके लिए विभिन्न कच्चे माल के उपयोग की आवश्यकता होती है, अंतिम उत्पाद में कोई अंतर नहीं होता है। उत्पाद का उपयोग समान अनुप्रयोगों के लिए और उसी तरीके से किया जाता है। दोनों प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके निर्मित अंतिम उत्पाद की विशेषताओं के बीच कोई अंतर नहीं है।
8. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबंधित देश से आयातित माल की वस्तु की तरह होता है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबंधित देश से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक गुणों, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन और माल के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। यद्यपि संबंधित वस्तुओं के उत्पादन के लिए विभिन्न विनिर्माण प्रक्रिया/प्रौद्योगिकियां शामिल हैं, अंतिम उत्पाद में तुलनीय विनिर्देश हैं और इसका परस्पर उपयोग किया जाता है। इसे देखते हुए, घरेलू उद्योग द्वारा विनिमत उत्पाद को भारत में आयातित उत्पाद की वस्तु के समान माना जाता है।
9. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत एचएस कोड 2905120

के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

#### घ. घरेलू उद्योग और स्थायी का दायरा

##### घ.1 अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तुत करना

10. घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि दीपक फेनोलिक्स लिमिटेड को जांच की अवधि के दौरान संबंधित वस्तुओं के आयात के कारण आवेदक द्वारा अयोग्य माना गया था। हालांकि, याचिकाकर्ता का मानना था कि वह दूसरे देश से सामान आयात करने के बावजूद पात्र है। दीपक फेनोलिक्स ने चीन जन गण से 2.12 मिलियन डॉलर का सामान आयात किया, जबकि याचिकाकर्ता ने कोरिया से 7.14 मिलियन डॉलर का आयात किया, जिसमें प्राधिकरण को प्रभावित करने के जानबूझकर प्रयास का आरोप लगाया गया। कोरिया से याचिकाकर्ता का लगातार आयात चीन से बचने और समान कीमतों पर अन्य देशों से आयात जारी रखने की रणनीति का संकेत देता है। यह घरेलू उद्योग भागीदार के लिए पात्रता मानदंड के बारे में चिंता पैदा करता है।

##### घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

11. घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र और स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण निम्नानुसार हैं:
- आवेदक के अलावा, भारत में संबंधित वस्तुओं का केवल एक अन्य घरेलू उत्पादक है, वह है, दीपक फेनोलिक्स लिमिटेड ("डीपीएल")।
  - डीपीएल ने जांच की अवधि के दौरान संबंधित देश से संबंधित वस्तुओं का आयात किया है। इस प्रकार, निर्माता को स्थिति निर्धारित करने के उद्देश्य से अयोग्य माना जाना चाहिए।
  - आवेदक ने जांच की अवधि के दौरान संबंधित देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और वह भारत में किसी भी आयातक या संबंधित देश के किसी निर्यातक से संबंधित नहीं है।
  - आयात गैर-अधीन देशों, मुख्य रूप से दक्षिण कोरिया से किए गए थे। पाटन रोधीनियमों के नियम 2 (बी) के अनुसार, एक आवेदक को घरेलू उद्योग का गठन करने के लिए अयोग्य माना जा सकता है यदि वह डंप की गई वस्तु का आयातक है। चूंकि डंपिंग जांच केवल संबंधित देश से आयात के लिए लागू होती है, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा अन्य देशों से किए गए आयात याचिकाकर्ता को घरेलू उद्योग बनाने से नहीं रोकते हैं।

व्यक्तियों	इकाई	2022-23
याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आयात	एमटी	***
भारत में उत्पादन	एमटी	***
भारत में मांग	एमटी	***
उत्पादन के संबंध में आयात	%	***
मांग के संबंध में आयात	%	***

- मौखिक सुनवाई के दौरान अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा बताई गई आयात की मात्रा को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया था। भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में आयात नगण्य है, जैसा कि ऊपर तालिका में दिखाया गया है।
- यदि डीपीएल को अपात्र माना जाता है तो आवेदक भारत में इस प्रकार की वस्तु का 100% उत्पादन करता है।
- यदि डीपीएल को पात्र माना जाता है, तो आवेदक अभी भी भारत में घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है और इस प्रकार, पाटन रोधीनियमों के नियम 2 (बी) और नियम 5 के अनुसार आवश्यकता को पूरा करता है।

### घ.3 प्राधिकरण द्वारा परीक्षा

12. नियमों का नियम 2 (बी) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

"(ख) 'घरेलू उद्योग' से वे घरेलू उत्पादक अभिप्रेत हैं जो संपूर्ण रूप से ऐसी वस्तु के विनिर्माण में लगे हुए हैं और उससे संबंधित कोई कार्यकलाप या वे जिनके उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा अनुपात है, सिवाय इसके कि जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों या स्वयं उसके आयातक हों, ऐसे मामले में 'घरेलू उद्योग' शब्द का अर्थ लगाया जा सकेगा बाकी उत्पादकों का जिक्र करते हुए।

13. वर्तमान जांच शुरू करने के लिए दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आवेदन दायर किया गया है। आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि भारत में संबंधित वस्तुओं का केवल एक अन्य उत्पादक है, जो दीपक फेनोलिक्स लिमिटेड है। डीपीएल ने संबंधित देश से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का समर्थन करते हुए एक पत्र प्रस्तुत किया है। यह नोट किया जाता है कि आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और वह भारत के किसी आयातक या संबंधित देश के किसी निर्यातक से संबंधित नहीं है।
14. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि दीपक फेनोलिक्स लिमिटेड (डीपीएल) ने जांच की अवधि के दौरान संबंधित देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है। यह दावा डीपीएल के बयान द्वारा समर्थित है और इसे डीजी सिस्टम डेटा के माध्यम से भी सत्यापित किया जाता है। चूंकि, डीपीएल ने संबंधित देश से पीयूसी का आयात किया है, प्राधिकरण स्थिति निर्धारित करने के उद्देश्य से डीपीएल को अयोग्य मानता है। तदनुसार, प्राधिकरण का मानना है कि इस जांच के उद्देश्य के लिए, आवेदक भारत में घरेलू उत्पादन का 100% हिस्सा है और नियमों के नियम 5 (3) के साथ पठित नियम 2 (बी) की स्थायी आवश्यकता को पूरा करता है।
15. उत्पादक/निर्यातक के इस दावे के जवाब में कि याचिकाकर्ताओं का कोरिया से लगातार आयात चीन से बचने और समान कीमतों पर आयात जारी रखने की रणनीति का सुझाव देता है, घरेलू उद्योग के लिए पात्रता मानदंड के बारे में चिंताएं पैदा करता है, प्राधिकरण नोट करता है कि शब्द "स्वयं इसके आयातक हैं" एडी नियमावली 1995 के नियम 2(बी) में उन घरेलू उत्पादकों को संदर्भित किया गया है जो कथित डंप की गई वस्तु के आयात में शामिल हैं। शब्द "उसके" स्पष्ट रूप से कथित डंप किए गए लेखों को संदर्भित करता है। इसके अलावा, उक्त नियम में "कथित डंप की गई वस्तु" डंपिंग के आरोपी देश अर्थात् विषय देश, जो वर्तमान जांच में चीन है, के माल से संबंधित है। चूंकि आवेदक ने चीन से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है, इसलिए इस जांच के लिए घरेलू उद्योग के रूप में आवेदक की पात्रता के संबंध में कोई प्रश्न नहीं है। प्राधिकरण ने सत्यापित किया कि दीपक फर्टिलाइजर्स ने कोरिया से \*\*\* मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं का आयात किया, जिसकी राशि \$\*\*\* मिलियन थी। जांच अवधि के दौरान ये आयात कुल आयात का \*\*\*% और कुल मांग का \*\*\*% प्रतिनिधित्व करते हैं। यह डेटा इंगित करता है कि कोरिया आरपी से आयात की मात्रा और मूल्य समग्र बाजार के संदर्भ में अपेक्षाकृत मामूली है, इस दावे को कमजोर करता है कि बहिष्करण का उद्देश्य जांच के नतीजे को प्रभावित करना था।
16. प्राधिकरण आगे नोट करता है कि स्थिति का निर्धारण करने के उद्देश्य से डीपीएल के उत्पादन को ध्यान में रखा जाता है, आवेदक पूरी तरह से भारत में घरेलू उत्पादन के बड़े अनुपात के लिए जिम्मेदार है और इस प्रकार, नियमों के नियम 5 (3) के साथ पठित नियम 2 (बी) की आवश्यकता को पूरा करता है।

### ड. गोपनीयता

#### ड.1 अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तुत करना

17. गोपनीयता के संबंध में अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा कोई प्रस्तुतियाँ नहीं की गई हैं।

#### ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण

18. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण इस प्रकार हैं:

क. झुहाई लॉन्ग सक्सेस केमिकल इंडस्ट्री कंपनी ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है क्योंकि उसने उत्पादित/बेचे गए उत्पादों की सूची, शेयरहोल्डिंग, उत्पादन प्रक्रिया, कर्मचारियों की संख्या और संबंधित पक्षों के विवरण गोपनीय होने का दावा किया है।

ख. (ख) मैसर्स फॉक्स केम पीटीई लिमिटेड और एसके केमिकल ट्रेडिंग (हांगकांग) लिमिटेड ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है क्योंकि उन्होंने संबंधित वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री में शामिल संबंधित पक्षों के साथ-साथ कंपनी के शेयरधारकों का खुलासा नहीं किया है।



### ड.3 प्राधिकरण द्वारा समीक्षा

19. पाटन रोधी नियमों के नियम 7 में निम्नानुसार प्रावधान है:

"7. गोपनीय जानकारी:

(1) नियम 6 के उपनियम (2), उपनियम (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में किसी बात के होते हुए भी, नियम 5 के उपनियम (1) के अधीन प्राप्त आवेदनों की प्रतियां, या अन्वेषण के दौरान किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर अभिहित प्राधिकारी को उपलब्ध कराई गई कोई अन्य जानकारी, नामित प्राधिकारी द्वारा अपनी गोपनीयता के बारे में संतुष्ट होने पर, उसके द्वारा ऐसा माना जाएगा और ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष के विशिष्ट प्राधिकरण के बिना किसी अन्य पार्टी को ऐसी कोई जानकारी प्रकट नहीं की जाएगी।

(2) अभिहित प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले इच्छुक पक्षकारों से अपेक्षा कर सकेगा कि वे उसका गैर-गोपनीय सारांश प्रस्तुत करें और यदि, ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष की राय में, ऐसी जानकारी सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, तो ऐसा पक्षकार अभिहित प्राधिकारी को उन कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकेगा कि संक्षेपण संभव क्यों नहीं है।

(3) उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि अभिहित प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध वांछित नहीं है या सूचना का आप्तकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने या उसके प्रकटीकरण को किसी सामान्यीकृत या सारांश रूप में प्राधिकृत करने के लिए या तो अनिच्छुक है तो वह ऐसी जानकारी की अवहेलना कर सकेगा।

20. गोपनीयता दावों की पर्याप्तता के संबंध में सभी इच्छुक पक्षों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई जानकारी की जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकरण ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है, जहां भी आवश्यक है और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है और अन्य इच्छुक पार्टियों को खुलासा नहीं किया गया है। जहां कहीं संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त गैर-गोपनीय विवरण उपलब्ध कराएं, जिसे सभी इच्छुक पक्षों को विधिवत परिचालित किया गया था।

### च. विविध मुद्दे

#### च.1 अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तुत करना

21. उत्पादक/निर्यातक का तर्क है कि घरेलू उद्योग यह साबित करने में विफल रहा है कि चीन बेंचमार्क कीमतें निर्धारित कर रहा है, खासकर जब विभिन्न देशों से आयात कीमतों को कम करता है। यह निर्धारित करने के लिए कोई स्पष्ट मानदंड नहीं है कि कौन सा देश पाटन रोधीजांच में बेंचमार्क सेट करता है, और मूल्य डेटा चीन जन गण, ताइवान, कोरिया आरपी, यूएसए और नीदरलैंड से महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव दिखाता है। चीनी निर्यातक अन्य देशों की तुलना में लगातार कम बेंचमार्क सेट नहीं करते हैं। मूल्य निर्धारण रणनीतियाँ बाजार की स्थितियों, मुद्रा में उतार-चढ़ाव और वैश्विक व्यापार की गतिशीलता से प्रभावित होती हैं। घरेलू उद्योग को हुई क्षति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी प्रमुख सोर्सिंग देशों से आयात का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। प्राधिकरण से आग्रह किया जाता है कि वह केवल चीन जन गण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सभी शामिल देशों में लगातार व्यापार उपायों की समीक्षा और लागू करे।
22. चीन पीआर के खिलाफ जांच याचिकाकर्ता के आवेदन के आधार पर शुरू की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से चीनी निर्यात पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसमें घरेलू उद्योग को मूल्य कम करने और भौतिक नुकसान का हवाला दिया गया था। हालांकि, चीन से आयात की कीमतें ताइवान, कोरिया, अमेरिका और नीदरलैंड के समान थीं, जो सामूहिक रूप से कुल आयात का 99% थीं। उत्पादक/निर्यातक का तर्क है कि उन सभी देशों के खिलाफ जांच शुरू की जानी चाहिए जिनकी आयात कीमतें चीन के समान हैं, विशेष रूप से वे जो 3% आयात मात्रा की सीमा को पूरा करते हैं। पाटन रोधी नियमों के अनुलग्नक II में कई देशों से आयात के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन अनिवार्य है जब डंपिंग का मार्जिन निर्यात मूल्य के 2% से अधिक हो, और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा कुल आयात का कम से कम 3% हो, या सामूहिक रूप से इन देशों का कुल आयात का 7% से अधिक हिस्सा हो।

23. यह भी तर्क दिया गया है कि इस मामले में चीन जैसे एक देश पर ध्यान केंद्रित करना, दूसरों पर विचार किए बिना मनमाना और भेदभावपूर्ण माना जा सकता है। इससे मूल्य में कमी और विभिन्न स्रोतों से घरेलू उद्योग को होने वाली हानि के मुद्दे का प्रभावी ढंग से समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए, प्राधिकरण से सभी निर्यातक देशों के व्यवहार का निष्पक्ष मूल्यांकन करने का आग्रह किया जाता है।
24. ताइवान, कोरिया, अमेरिका और नीदरलैंड से व्यक्तिगत रूप से आयात 3% सीमा से अधिक है, जो चीन सहित कुल आयात का 99% है। वर्तमान जांच सभी संबंधित देशों को शामिल नहीं करके विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन कर सकती है। पाटन रोधीकानूनों का पालन करने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक जांच की आवश्यकता है।
25. यह प्रस्तुत किया गया है कि व्यापार उपचार जांच के लिए परिचालन प्रथाओं के मैनुअल के अनुच्छेद 11.7.2 के अनुसार, वर्तमान जांच में एक संचयी मूल्यांकन की आवश्यकता है। मानदंड यह निर्धारित करते हैं कि ऐसा मूल्यांकन तब किया जाना चाहिए जब अलग-अलग देशों से आयात समान उत्पाद की आयात मात्रा के 3% से अधिक हो, और सामूहिक रूप से 7% से अधिक हो। वर्तमान जांच में ये शर्तें पूरी होती हैं। इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाता है कि अन्य सभी देशों से डंपिंग का मार्जिन चीन जन गण के समान सीमा के भीतर गिरने की उम्मीद है, उनकी सीआईएफ कीमतों में समानता को देखते हुए। इसलिए, एक संपूर्ण और कानूनी रूप से ध्वनि जांच सुनिश्चित करने के हित में, यह अनुशंसा की जाती है कि प्राधिकरण वर्तमान जांच में संचयी मूल्यांकन के साथ आगे बढ़े।
26. उत्पादक/निर्यातक यह भी तर्क देते हैं कि केवल चीन के खिलाफ जांच पर ध्यान केंद्रित करने से घरेलू उद्योग को नुकसान पूरी तरह से कम नहीं होगा। ताइवान, कोरिया आरपी, यूएसए और नीदरलैंड जैसे देशों की कीमतें अतीत में चीन की तुलना में प्रतिस्पर्धी या कम रही हैं। अनुचित मूल्य वाले आयातों के कारण होने वाली क्षति का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए, सभी संबंधित देशों को शामिल करते हुए एक संपूर्ण जांच आवश्यक है। यह व्यापक दृष्टिकोण किसी भी पाटन रोधीउपायों का उचित और समान अनुप्रयोग सुनिश्चित करता है। सभी देशों को शामिल करने में विफलता के परिणामस्वरूप चल रही अनुचित प्रतिस्पर्धा और घरेलू उद्योग के लिए अपर्याप्त सुरक्षा हो सकती है।

## च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण

27. जांच का लक्ष्य चीन से आयात पर पाटन रोधी शुल्क लगाना है, जो भारतीय बाजार में प्राथमिक मूल्य निर्धारक है। दक्षिण कोरिया, ताइवान, अमेरिका और नीदरलैंड जैसे देशों से महत्वपूर्ण आयात के बावजूद, जांच अवधि के दौरान केवल चीन के आयात में वृद्धि हुई है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर अन्य प्रमुख देशों से आयात में गिरावट आई है।

देशों	2021-22	2022-23	परिवर्तन	
			आयतन	%
चीन	38,364	76,040	37,676	98%
ताइवान	23,152	13,890	-9,262	-40%
कोरिया	36,759	14,860	-21,899	-60%
संयुक्त राज्य अमेरिका	5,691	8,763	3,072	54%
नीदरलैंड	7,457	4,498	-2,959	-40%
अन्य देशों के लिए कुल	8,188	1,478	-6,710	-82%
इन देशों के लिए कुल	81,247	43,489	-37,758	

28. संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात अपेक्षाकृत कम है, 8,763 मीट्रिक टन, जो भारत के कुल आयात का केवल 6% और इसकी मांग का 4% है। इसके विपरीत, जबकि चीन ने अपने आयात में 37,676 मीट्रिक टन की वृद्धि की, अन्य देशों ने सामूहिक रूप से 37,758 मीट्रिक टन खो दिया, यह दर्शाता है कि चीनी उत्पादकों ने अन्य देशों के आपूर्तिकर्ताओं को बदल दिया। मासिक आंकड़ों से पता चलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के आयात केवल जांच

अवधि की तीसरी तिमाही में हुए। इसके अतिरिक्त, चीन का औसत आयात मूल्य सभी गैर-अधीन देशों की तुलना में कम था, जिससे चीनी उत्पादों द्वारा अन्य देशों से आयात का पूर्ण प्रतिस्थापन हुआ।

29. आवेदक ने आगे कहा कि प्राधिकरण को यह आकलन करना चाहिए कि क्या चीन से डंप किया गया आयात नुकसान पहुंचाने का एक प्रमुख कारक है। डंप किए गए आयात के लिए क्षति का एकमात्र या प्रमुख कारण होना आवश्यक नहीं है; उन्हें केवल योगदान कारकों में से एक होना चाहिए। यूरोपीय समुदायों के मामले में - ब्राजील से निंदनीय कास्ट आयरन स्लैब या पाइप फिटिंग पर पाटन रोधीशुल्क [डीएस 219], पैनल ने निर्धारित किया कि भले ही अन्य देशों से आयात ने भौतिक क्षति में योगदान दिया हो, वे डंपिंग और क्षति के बीच कारण लिंक को नकारते नहीं हैं।

7.367 अपने निर्धारण में, यूरोपीय समुदाय ने डंप किए गए आयातों के अलावा कुछ कारकों की पहचान की, जो संभावित रूप से घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा रहे थे, जिसमें तीसरे देशों से आयात शामिल थे जो जांच के अधीन नहीं थे; खपत और प्रतिस्थापन में गिरावट। व्यक्तिगत रूप से इन कारकों में से प्रत्येक के संबंध में, यूरोपीय समुदाय ने एक अलग परीक्षा आयोजित की और पाया कि यह "ऐसा नहीं है कि सामुदायिक उद्योग को हुई भौतिक क्षति के लिए किसी भी महत्वपूर्ण तरीके से योगदान दिया गया है" (खपत में गिरावट); कि इसने "कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं" (निर्यात प्रदर्शन) किया या कि "कोई महत्वपूर्ण प्रभाव" नहीं हो सकता था (संबंधित उत्पाद का स्वयं का आयात), कि यह क्षति (प्रतिस्थापन) में महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे सकता है, या (उन देशों से आयात के मामले में जो जांच के अधीन नहीं हैं) "भले ही अन्य तीसरे देशों के आयात ने सामुदायिक उद्योग को हुई भौतिक क्षति में योगदान दिया हो, इसके द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि वे डंपिंग और पाए गए क्षति के बीच कारण लिंक को तोड़ने वाले ऐसे नहीं हैं"। **यूरोपीय समुदाय ने निष्कर्ष निकाला कि घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में योगदान देने वाले किसी भी अन्य कारक "डंप किए गए आयात और क्षति के बीच आकस्मिक लिंक को तोड़ने के लिए नहीं" थे।**

7.368 इसी निर्धारण के इन पहलुओं से हमें संकेत मिलता है कि यूरोपीय समुदायों ने व्यक्तिगत रूप से संबंधित कारण कारकों का विश्लेषण किया और इनमें से प्रत्येक कारण कारकों के व्यक्तिगत प्रभावों की पहचान की। प्रत्येक कारक के संबंध में, यूरोपीय समुदाय ने निष्कर्ष निकाला कि क्षति में योगदान की सीमा महत्वपूर्ण नहीं थी, या, एक मामले में, यह अनुमान लगाया गया था कि, भले ही प्रभाव महत्वपूर्ण हो, यह डंप किए गए आयात और भौतिक क्षति के बीच "कारण लिंक को तोड़ने" जैसा नहीं होगा। यूरोपीय समुदाय का समग्र निष्कर्ष यह था कि इनमें से किसी भी कारक का प्रभाव नहीं था जो डंप किए गए आयात और भौतिक क्षति के बीच कारण लिंक को तोड़ने वाला था।

7.369 हम निश्चित रूप से सैद्धांतिक संभावना से अवगत हैं कि एक कार्य-कारण पद्धति जो अलग-अलग क्षति कारकों के बीच अंतर करती है, इस संभावना को समायोजित नहीं कर सकती है कि कई "महत्वहीन कारक" सामूहिक रूप से क्षति का एक महत्वपूर्ण कारण बन सकते हैं जैसे कि डंप किए गए आयात और क्षति के बीच की कड़ी को अलग करना। हालांकि, इसी पद्धति - जिसे हम इन कारण कारकों में से प्रत्येक के प्रभावों और डंप किए गए आयातों के बीच अलग करने और अंतर करने के लिए समझते हैं, जिसमें एक परीक्षा के माध्यम से शामिल है कि क्या प्रत्येक कारण कारक के प्रभावों की सीमा ऐसी है कि इसके प्रभावों को अलग करना और अलग करना आवश्यक है - उन कारकों के प्रभावों को पूरी तरह से एक साथ और अप्रभेद्य नहीं छोड़ता है।

30. संयुक्त राज्य अमेरिका के 7.253 का अनुच्छेद 7.250 - जापान से कुछ हॉट-रोल्ड स्टील उत्पादों पर पाटन रोधीउपाय [डीएस 184] यह भी बताता है कि एडी समझौते के अनुच्छेद 3.5 में यह अनिवार्य है कि अधिकारी डंप किए गए आयात और घरेलू उद्योग को नुकसान के बीच एक कारण लिंक प्रदर्शित करें। इसमें सभी प्रासंगिक साक्ष्यों की गहन समीक्षा और नुकसान पहुंचाने वाले अन्य कारकों पर विचार करना शामिल है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन अन्य कारकों से होने वाली चोटों को गलत तरीके से डंप किए गए आयात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है। आवश्यकता सरलीकृत निष्कर्षों से बचने पर जोर देती है और पुष्टि करती है कि अन्य कारकों से चोटों को डंप किए गए आयात और सामग्री की क्षति के बीच कारण लिंक को बाधित नहीं करना चाहिए। *संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्णय - अटलांटिक सैल्मन* प्रासंगिक बना हुआ है, यह पुष्टि करते हुए कि डंप किए गए आयात के लिए चोटों के गैर-एट्रिब्यूशन का सिद्धांत जापान के मूल पाठ परिवर्तनों के दावों के बावजूद अपरिवर्तित है।

31. किसी एक देश से आयात पर पाटन रोधीशुल्क लगाया जा सकता है यदि उन आयातों से घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है। प्रमुख कानूनी आवश्यकता यह है कि डंप किए गए आयात क्षति के कारणों में से एक होना चाहिए। यूरोपीय संघ ने अन्य देशों से महत्वपूर्ण आयात के बावजूद अलग-अलग देशों से आयात पर इस तरह के शुल्क लगाए हैं। उदाहरण के लिए:

- **चीन से कैल्शियम सिलिकाॉन:** हालांकि ब्राजील और गैर-अधीन देशों से आयात महत्वपूर्ण थे, यूरोपीय आयोग ने ब्राजील और अन्य स्रोतों की तुलना में इसकी उच्च मात्रा और क्षति पर अधिक प्रभाव का हवाला देते हुए चीन पर ध्यान केंद्रित किया।
- **रूस से बिर्च प्लाईवुड:** बेलारूस और यूक्रेन से आयात मौजूद होने के बावजूद, यूरोपीय संघ ने बाजार में अन्य आयातों की सीमित उपस्थिति के कारण केवल रूस को लक्षित किया।

32. अभ्यास इस बात की पुष्टि करता है कि पाटन रोधीशुल्क अन्य सभी देशों से आयात पर विचार किए बिना किसी एक देश से क्षति को संबोधित कर सकते हैं, भले ही वे आयात महत्वपूर्ण हों।

33. इसके अलावा, कानून पाटन रोधीजांच के लिए विषय देशों का चयन करने के लिए मानदंडों की रूपरेखा नहीं देता है। यह निर्दिष्ट करता है कि जांच को समाप्त कर दिया जाना चाहिए यदि किसी विषय देश से आयात व्यक्तिगत रूप से 3% या संचयी रूप से 7% से कम है। नियम चयन मानदंडों के बजाय समाप्ति की शर्तों को संबोधित करते हैं। संचयी मूल्यांकन पर नियमों का अनुलग्नक II केवल तभी लागू होता है जब एक से अधिक देशों की एक साथ जांच की जाती है। चूंकि वर्तमान मामले में केवल एक देश शामिल है, इसलिए यह नियम लागू नहीं होता है। इसके अलावा, अन्य देशों से डंपिंग का कोई सबूत नहीं है, जो उन्हें जांच में शामिल करने के लिए आवश्यक है।

### च.3 प्राधिकरण द्वारा समीक्षा

34. कानून में दीक्षा के खराब होने के संबंध में सभी इच्छुक पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों का विश्लेषण लागू नियमों के ढांचे के भीतर किया गया था। इस संबंध में, एडी नियम, 1995 के नियम 14 में उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनके तहत जांच समाप्त की जाएगी। नियम 14 (डी) की आवश्यकता है कि जांच को समाप्त कर दिया जाना चाहिए यदि किसी विशिष्ट देश से आयात समान उत्पाद के कुल आयात के तीन प्रतिशत से कम के लिए खाता है, जब तक कि व्यक्तिगत रूप से आयात के तीन प्रतिशत से कम योगदान करने वाले देशों ने सामूहिक रूप से कुल आयात मात्रा के सात प्रतिशत से अधिक के लिए खाते नहीं हैं।

35. इस संदर्भ में प्राधिकरण का मानना है कि ऐसा कोई प्रचलित विशिष्ट कानून नहीं है जो किसी एक देश के विरुद्ध जांच शुरू करने पर रोक लगाता हो, भले ही अन्य देशों से आयात पर्याप्त मात्रा में हो। इसलिए, वर्तमान जांच किसी भी कानूनी मानकों का उल्लंघन नहीं करती है क्योंकि यह क्षति का आकलन करने के लिए पूरी तरह से चीनी आयात पर केंद्रित है।

36. इच्छुक पार्टियों के आरोपों के प्रकाश में कि अन्य देशों ताइवान, कोरिया, अमेरिका और नीदरलैंड से आयात महत्वपूर्ण थे और घरेलू उद्योग का तर्क था कि चीन बाजार मूल्य निर्धारित कर रहा था, जांच प्राधिकरण ने सावधानीपूर्वक जांच की कि क्या ताइवान, कोरिया, अमेरिका और नीदरलैंड से आयात की तुलना में चीनी कीमतें कम या अधिक थीं। विशेष रूप से, इन देशों से आयात की मात्रा जांच की अवधि (पीओआई) के दौरान न्यूनतम सीमा से अधिक हो गई। इस उदाहरण में, प्राधिकरण ने विशिष्ट परिस्थितियों का अवलोकन किया है, जिन्हें बाद के अनुच्छेदग्राफ में संबोधित किया गया है।

37. प्राधिकरण ने आयात कीमतों की व्यापक तुलना की, समय के साथ महत्वपूर्ण मूल्य उतार-चढ़ाव के लिए मासिक आधार पर डेटा का विश्लेषण किया। एक मजबूत मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए, चीन से संबंधित आयात मात्रा को ध्यान में रखते हुए चीन और अन्य प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से प्रत्येक के बीच एक भारित औसत मूल्य अंतर की गणना की गई थी।

## चीन और अन्य देशों की माह-वार मूल्य प्रवृत्ति

मासिक मूल्य विश्लेषण										
महीना	चीन		ताइवान		कोरिया आरपी		संयुक्त राज्य अमेरिका		नीदरलैंड	
	मात्रा	रु./एमटी	मात्रा	रु./एमटी	मात्रा	मात्रा	मात्रा	रु./एमटी	मात्रा	रु./एमटी
अप्रैल-22	9,547	81,774	173	97,951	1,399	86,231	-	-	12	-
मई-22	6,488	89,025	1,930	88,603	-	-	-	-	12	-
जून-22	8,097	88,956	1,697	95,450	1,998	88,378	-	-	1,502	84,859
जुलाई-22	8,043	89,883	1,003	88,137	-	-	-	-	12	-
अगस्त-22	-	-	13	1,55,424	-	-	-	-	-	-
सितम्बर-22	7,463	77,139	-	-	2,969	84,073	-	-	-	-
अक्टूबर-22	8,322	77,162	1,785	77,085	1,940	78,930	-	-	1,062	85,914
नवम्बर 22	4,905	77,702	1,016	79,163	-	-	1,504	82,877	12	-
दिसम्बर-22	7,607	78,655	2,662	74,524	985	85,012	3,960	79,735	1,539	84,294
जनवरी-23	2,953	77,757	1,039	74,251	115	1,06,451	19	-	6	-
फरवरी-23	4,904	76,232	742	77,500	112	1,00,995	321	76,709	12	-
मार्च-23	4,094	79,136	1,805	77,838	5,091	77,483	2,960	74,883	6	-
कुल	72,423	81,828	13,864	81,635	14,610	82,259	8,763	80,215	4,177	93,156

चीन और अन्य देशों (ताइवान, कोरिया, अमेरिका और नीदरलैंड) के बीच मासिक और भारित औसत मूल्य अंतर  
(रु./एमटी)

महीना	चीन द्वारा निर्यात की गई मात्रा (मीट्रिक टन)	ताइवान	कोरिया	संयुक्त राज्य अमेरिका	नीदरलैंड
अप्रैल-22	9,547	16,177	4,457	-	-
मई-22	6,488	-422	-	-	-
जून-22	8,097	6,494	-578	-	-4,096
जुलाई-22	8,043	-1,746	-	-	-
अगस्त-22	-	-	-	-	-
सितम्बर-22	7,463	-	6,934	-	-
अक्टूबर-22	8,322	-76	1,768	-	8,752
नवम्बर-22	4,905	1,461	-	5,176	-
दिसम्बर-22	7,607	-4,131	6,357	1,080	5,639
जनवरी-23	2,953	-3,506	28,694	-	-
फरवरी-23	4,904	1,268	24,763	478	-
मार्च-23	4,094	-1,298	-1,653	-4,253	-
भारित औसत मूल्य में कटौती	72,423	2,153	4,862	256	1,140

38. उपरोक्त विश्लेषण से पता चला कि चीन से आयात मूल्य वर्तमान पीओआई में ताइवान, कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और नीदरलैंड की तुलना में कम थे। इसके अलावा, यह कम कीमत वाले चीनी आयात थे जिन्होंने अन्य देशों को भी अपनी कीमतों कम करने के लिए मजबूर किया। यह खोज दृढ़ता से सुझाव देती है कि चीनी आयात की कीमतों ने समग्र बाजार मूल्य पर नीचे की ओर दबाव डाला।
39. इसके अलावा, चीनी निर्यात से मेल खाने के लिए अपनी कीमतों को समायोजित करके प्रतिस्पर्धी बने रहने के अन्य देशों के प्रयासों के बावजूद, उन्होंने पीओआई के दौरान आयात मात्रा में गिरावट का अनुभव किया। यह देखा गया है कि जहां चीन के आयात में लगभग 37,000 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई, वहीं प्रमुख निर्यातक देशों से आयात में सामूहिक रूप से 31,000 मीट्रिक टन की गिरावट आई। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि चीनी आयात की कम कीमतें न केवल अन्य आपूर्तिकर्ताओं की कीमतों को कम करती हैं, बल्कि उनकी मात्रा और बाजार हिस्सेदारी को भी काफी प्रभावित करती हैं।

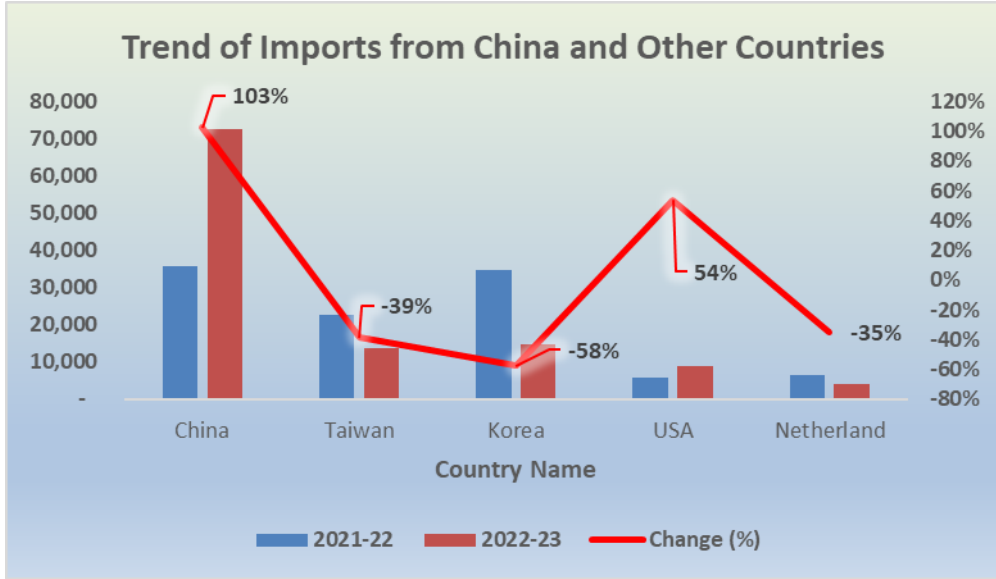
देशों	मात्रा (MT)				मूल्य (₹./यूनिट)			
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
चीन जन. गण.	78,685	52,332	35,758	72,423	50,272	92,645	82,240	81,828
ताइवान	7,676	19,859	22,593	13,864	55,305	86,532	83,789	81,635
कोरिया आरपी	28,823	34,691	34,547	14,610	52,336	89,061	80,955	82,259
यू.एस.ए.	9,862	18,952	5,695	8,763	54,958	81,783	79,344	80,215
नीदरलैंड	5,162	5,033	6,440	4,177	53,347	93,117	89,754	93,156

40. प्राधिकरण ने डीजी सिस्टम्स से आयात आंकड़ों की जांच की और यह पाया कि चीन से आयात में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर अन्य देशों से आयातों में काफी कमी आई है। इसे नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है। यूएसए से आयात के संबंध में, यह देखा गया है कि यूएसए द्वारा निर्यात नियमित नहीं थे और यह दिसंबर, 2022 से मार्च 2023 के बीच पीओआई के अंत में ही हुआ। पीओआई के दौरान चीन से आयातों में 100% से अधिक की महत्वपूर्ण वृद्धि और साथ-साथ अन्य देशों से आयातों में गिरावट स्पष्ट रूप से बाजार को नियंत्रित करने वाले और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंचाने वाले चीनी निर्यातकों/उत्पादकों के प्रभुत्व को दर्शाती है। इसके अलावा, अन्य देशों के खिलाफ जांच शुरू नहीं करने का निर्णय घरेलू उद्योग पर चीनी आयात द्वारा लगाए गए संभावित नुकसान को नकारता नहीं है।

#### चीन और अन्य देशों से आयात की प्रवृत्ति

आयात	2021-22	2022-23	परिवर्तन (%)
चीन	35,758	72,423	103%
ताइवान	22,593	13,864	-39%
कोरिया	34,547	14,610	-58%
संयुक्त राज्य अमेरिका	5,695	8,763	54%
नीदरलैंड	6,440	4,177	-35%

41. चीन और अन्य देशों से आयात की प्रवृत्ति का एक चित्रमय प्रतिनिधित्व भी चीन से आयात में उल्लेखनीय वृद्धि और अन्य देशों से आयात में गिरावट को दर्शाने के लिए निम्नानुसार दर्शाया गया है, विशेष रूप से भारत में कुल आयात का 3% से अधिक के लिए लेखांकन।



42. मूल्य निर्धारण डेटा, बाजार हिस्सेदारी के रुझान और घरेलू उद्योग पर समग्र प्रभाव की परीक्षा यह स्थापित करती है कि चीनी आयात सामग्री की क्षति का प्राथमिक और प्रमुख कारण था।

छ. बाजार अर्थव्यवस्था उपचार (एमईटी), सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिनका निर्धारण

#### छ.1 अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तुतियाँ

43. 11 दिसंबर, 2016 के बाद, यानी चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल की समाप्ति के बाद, भारत के बुनियादी पाटन रोधीविनियम घरेलू कीमतों और लागत के आधार पर चीनी निर्यात करने वाले उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य स्थापित नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि भारत के पास अब गैर-बाजार अर्थव्यवस्था पद्धति का उपयोग करके चीनी उत्पादों की पाटन रोधीजांच में सामान्य मूल्य की गणना करने का कानूनी आधार नहीं है। यदि भारत अनुपालन नहीं करता है, तो चीन जन गण कानून को चुनौती दे सकता है, क्योंकि यह भारत के डब्ल्यूटीओ दायित्वों के साथ असंगत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय डब्ल्यूटीओ नियमों के अनुसार पाटन मार्जिनकी गणना के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए बाध्य है।

44. चीन पीआर को अपने बाजार अर्थव्यवस्था के विकास के आधार पर "बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा" दिया जाना चाहिए, और सामान्य मूल्य गणना पाटन रोधीसमझौते के अनुच्छेद 2 का पालन करना चाहिए, कंपनी द्वारा अपनी प्रतिक्रिया में दायर डेटा का उपयोग करना।

#### छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

45. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार, सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और डंपिंग माजन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी गई हैं

क. चीन पीआर को चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (ए) (आई) के अनुसार एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए, और सामान्य मूल्य नियमों के अनुलग्नक I के अनुच्छेद 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

ख. विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों को केवल चीन में घरेलू कीमतों या लागतों का उपयोग करने की आवश्यकता है यदि निर्माता साबित करते हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति उनके उद्योग पर लागू होती है। चूंकि उत्पादकों ने यह प्रदर्शन नहीं किया है, इसलिए नामित प्राधिकारी को सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए चीन की घरेलू कीमतों या लागतों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। यह दृष्टिकोण हाल की जांचों में चीन के नामित प्राधिकरण के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में व्यवहार के अनुरूप है, जिसमें चीन से इलेक्ट्रिक इंसुलेटर पर पाटन रोधीउपायों की सूर्यास्त समीक्षा शामिल है (केस नंबर 7/44/2018-डीजीटीआर)।

ग. कोरिया क्षेत्रीय गणराज्य से भारत के अलावा अन्य देशों को निर्यातों के एफओबी मूल्य के आधार पर संबंधित देश के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है। ऐसी कीमतों को बंदरगाह खर्च, बैंक शुल्क और अंतर्देशीय माल ढुलाई के लिए समायोजित किया जाता है।

- घ. वैकल्पिक रूप से, आवेदक ने भारत में देय मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण भी किया है जो बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और उचित लाभ के लिए विधिवत समायोजित है।
- ङ. आवेदक ने डीजीसीआई एंड एस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार निर्यात मूल्य निर्धारित किया है। समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बंदरगाह व्यय, बैंक शुल्क और अंतर्देशीय माल ढुलाई के लिए समायोजन किया गया है।
- च. डंपिंग मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

### छ.3 प्राधिकरण द्वारा समीक्षा

46. प्राधिकरण ने संबंधित देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी थी जिसमें उन्हें प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से सूचना उपलब्ध कराने की सलाह दी गई थी। निर्यातक की प्रश्नावली का जवाब झुहाई लॉन्ग सक्सेस केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, फॉक्स केम पीटीई लिमिटेड और एसके केमिकल ट्रेडिंग (एचके) लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है।

#### छ.3.1 सामान्य मूल्य का निर्धारण

##### बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति की परीक्षा

47. प्राधिकरण ने संबंधित देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी थी, जिसमें उन्हें प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से जानकारी प्रदान करने की सलाह दी गई थी। किसी भी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था के उपचार का दावा करने के लिए पूरक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। तदनुसार, चीन जन गण से उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य नीचे के रूप में निर्धारित किया गया है।

48. विश्व व्यापार संगठन में चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 15 निम्नानुसार प्रदान करता है:

"GATT 1994 का अनुच्छेद VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता 1994 ("पाटन रोधीएग्रीमेंट") के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन पर समझौता और SCM समझौता निम्नलिखित के अनुरूप विश्व व्यापार संगठन के सदस्य में चीनी मूल के आयात से जुड़ी कार्यवाही में लागू होगा:

(क) गैट 1994 के अनुच्छेद VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत मूल्य तुलनीयता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य जांचाधीन उद्योग के लिए या तो चीनी कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा अथवा ऐसी कार्यप्रणाली का उपयोग करेगा जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ कड़ी तुलना पर आधारित न हो

(i) यदि जांच के अधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रबल है, तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य तुलनीयता निर्धारित करने में जांच के तहत उद्योग के लिए चीनी कीमतों या लागतों का उपयोग करेगा;

(ii) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य ऐसी पद्धति का प्रयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ कड़ाई से तुलना पर आधारित न हो यदि जांचाधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह नहीं दर्शा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में इस प्रकार के उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति विद्यमान है।

(बी) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के तहत कार्यवाही में, अनुच्छेद 14 (ए), 14 (बी), 14 (सी) और 14 (डी) में वर्णित सब्सिडी को संबोधित करते समय, एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे; हालांकि, यदि उस आवेदन में विशेष कठिनाइयां हैं, तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य सब्सिडी लाभ की पहचान करने और मापने के लिए कार्यप्रणाली का उपयोग कर सकता है जो इस संभावना को ध्यान में रखता है कि चीन में मौजूदा नियम और शर्तें हमेशा उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य को चीन के बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के प्रयोग पर विचार करने से पहले ऐसे प्रचलित निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।



(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य पाटन रोधीप्रथाओं पर समिति को उप-अनुच्छेद (ए) के अनुसार उपयोग की जाने वाली पद्धतियों को अधिसूचित करेगा और सब्सिडी और काउंटरवेलिंग उपायों पर समिति को उप-अनुच्छेद (बी) के अनुसार उपयोग की जाने वाली पद्धतियों को अधिसूचित करेगा।

(घ) एक बार चीन ने डब्ल्यूटीओ के आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत यह स्थापित कर दिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, उपअनुच्छेद (ए) के प्रावधानों को समाप्त कर दिया जाएगा, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में परिग्रहण की तारीख के अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था मानदंड शामिल हों। किसी भी स्थिति में, उप-अनुच्छेद (ए) (ii) के प्रावधान परिग्रहण की तारीख के 15 साल बाद समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा, चीन को डब्ल्यूटीओ सदस्य के आयात के राष्ट्रीय कानून के अनुसार स्थापित करना चाहिए, कि किसी विशेष उद्योग या क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रबल होती है, उप-अनुच्छेद (ए) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रावधान अब उस उद्योग या क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे।

49. एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में चीन जन गण का उपचार केवल अनुच्छेद 15 (ए) (ii) से नहीं उपजा है – बल्कि अनुच्छेद 15 के शेष पाठ यानी उप-अनुच्छेद (ए), साथ ही साथ जीएटीटी 199435 के अनुच्छेद VI और डब्ल्यूटीओ पाटन रोधी समझौते के अनुच्छेद 2.2.1.1 में निर्धारित व्यापक नियमों से भी प्रवाहित होता है। पाटन रोधीएग्रीमेंट के गैट अनुच्छेद VI और अनुच्छेद 2.2.1.1 के साथ पठित चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 से उभरने वाले वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय ढांचे के अनुसार, चीन जन गण को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में मानने में कोई प्रतिबंध नहीं है। यह ध्यान दिया जाता है कि हालांकि अनुच्छेद 15 (ए) (ii) समाप्त हो गया है, डब्ल्यूटीओ में चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (ए) (i) के साथ पढ़े गए एंटी डंपिंग समझौते के अनुच्छेद 2.2.1.1 से संकेत मिलता है कि चीन जन गण के उत्पादकों / निर्यातकों को यह साबित करने की आवश्यकता हो सकती है कि चीन जन गण में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति मौजूद है। इसके अलावा, एडी नियमों के अनुलग्नक I के अनुच्छेद 8 में निर्धारित किया गया है कि कोई भी देश जिसे गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में निर्धारित किया गया है या माना गया है, उसे गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाता है। ऐसे देश के निर्यातक प्राधिकरण द्वारा जारी पूरक प्रश्नावली के उत्तर के रूप में एडी नियमों के अनुलग्नक-1 के अनुच्छेद 8 (3) में निर्धारित जानकारी/साक्ष्य प्रदान करके इस तरह के अनुमान का खंडन कर सकते हैं। इसलिए, उत्पादकों/निर्यातकों पर यह साबित करने का भार है कि विषय देश में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रबल है।
50. प्राधिकरण के पास चीन जन गण को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में मानने का एक सतत अभ्यास है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जनसंपर्क के प्रत्युत्तर देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों ने इस धारणा पर विवाद करने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था उपचार/अनुपूरक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है कि चीन जन गण में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, इसलिए नियमों के अनुबंध-1 के अनुच्छेद 7 के प्रावधानों के अनुसार सामान्य मूल्य संगणना की जानी अपेक्षित है। जो निम्नानुसार पढ़ता है:

"7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, सामान्य मूल्य बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, या ऐसे तीसरे देश से अन्य देशों में कीमत, भारत सहित या जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर, जिसमें वास्तव में भुगतान की गई कीमत या भारत में देय उत्पाद के लिए शामिल है, उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए यदि आवश्यक हो तो विधिवत समायोजित। संबंधित देश के विकास के स्तर और प्रथम उद्योग को ध्यान में रखते हुए नामित प्राधिकारी द्वारा उचित तरीके से एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश का चयन किया जाएगा, और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी भी विश्वसनीय जानकारी का उचित ध्यान रखा जाएगा। खातों समय सीमा के भीतर लिया जाएगा, जहां उचित हो, किसी भी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश के संबंध में किसी भी तरह के मामले में किए गए जांच की। जांच के पक्षकारों को बिना किसी अनुचित देरी के बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश के उपरोक्त चयन के बारे में सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियों की पेशकश करने के लिए उचित समय दिया जाएगा।

51. चीन पीआर के लिए सामान्य मूल्य भारत में देय मूल्य के आधार पर निर्धारित किया गया है, भारत में उत्पादन की लागत के अनुसार गणना की जाती है, विधिवत समायोजित, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ के लिए। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे डंपिंग माजन तालिका में दर्शाया गया है।

#### निर्यात मूल्य का निर्धारण

52. निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातकों की प्रश्नावली के जवाब दाखिल किए हैं:

i. झुहाई लॉन्ग सक्सेस केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड



## ज. क्षति का आकलन और कारण संबंध

### ज.1 अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तुतियाँ

57. घरेलू उद्योग की क्षति चीन जनगण से आयात के अलावा अन्य कारकों के कारण हुई है। यदि कोई क्षति लगती है, तो महानिदेशक को घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाने वाले ज्ञात कारकों की जांच करनी चाहिए।
58. अमेरिका में अपीलिय निकाय – हॉट-रोल्ड स्टील ने फैसला सुनाया कि जांच अधिकारियों को अन्य ज्ञात कारकों के कारण होने वाली क्षति का आकलन करना चाहिए और डंप किए गए आयात के हानिकारक प्रभावों को अन्य कारकों से अलग करना चाहिए। इसके लिए पाटित आयातों के हानिकारक प्रभावों से भिन्न अन्य कारकों के हानिकारक प्रभावों की प्रकृति और सीमा का संतोषजनक स्पष्टीकरण अपेक्षित है। यह महत्वपूर्ण है कि घरेलू बाजार को नुकसान पहुंचाने वाले अन्य कारकों को खारिज करने से पहले महानिदेशक द्वारा गैर-एट्रिब्यूटिव कारकों का विस्तार से विश्लेषण किया जाए। याचिकाकर्ता को हुई क्षति का निर्धारण करने के लिए, तीन मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए: अन्य कारकों के प्रभाव का विश्लेषण करना, याचिकाकर्ता पर उनके प्रभाव की सीमा का निर्धारण करना और किसी भी कारक के प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण करना।
59. व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) की अपने कम शुल्क नियम और गैर-हानिकारक मूल्य गणना के लिए आलोचना की जाती है, जिसे अत्यधिक बढ़ा हुआ माना जाता है और वास्तविक स्थितियों पर आधारित नहीं है। कानून में गैर-हानिकारक मूल्य पर पहुंचने के लिए उचित रिटर्न की आवश्यकता होती है, और डीजीटीआर को उद्योग द्वारा अर्जित पूंजी नियोजित रिटर्न (आरओसीई) को अपनाना चाहिए जब उचित लाभ मार्जिन के रूप में डंपिंग का कोई आरोप नहीं था।
60. 22% आरओसीई गलत है क्योंकि यह नियोजित पूंजी के निवल मूल्य वाले हिस्से पर 22% से अधिक रिटर्न प्रदान करता है, जो वैश्विक मंदी के दौरान स्वीकार्य नहीं है। डीजीटीआर के 22% आरओसीई को भी अनुचित माना जाता है, क्योंकि इसे भारत सरकार द्वारा ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर, 1987 में पेश किया गया था, जिसे विशेष रूप से बल्क ड्रग्स की कीमतें तय करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। 22% आरओसीई को 37 साल बाद उचित नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ब्याज दरें और कॉर्पोरेट टैक्स कम हो गए हैं। डीजीटीआर घरेलू उद्योग को अनुचित संरक्षण दे रहा है। इसके अलावा, ब्रिजस्टोन टायर विनिर्माण और अन्य के मामले में, ब्रिजस्टोन टायर विनिर्माण और अन्य के मामले में। v. नामित प्राधिकारी, एलडी सीईएसटीएटी ने देखा कि प्राधिकरण द्वारा अपनाया गया 22% आरओसीई का मूल्य सही नहीं है।

### ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

61. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारण लिंक के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियां दी गई हैं
- भारत में आयात निरपेक्ष रूप से और भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में बढ़ा है।
  - मांग में वृद्धि की तुलना में आयात में काफी अधिक दर से वृद्धि हुई है। विषय आयातों ने भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से के साथ-साथ अन्य देशों से आयातों को भी ले लिया है।
  - विषय आयात अन्य देशों के निर्यातकों को भारत को निर्यात की कीमतों को कम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।
  - आयात काफी कम हो रहा है और घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव डाल रहा है।
  - जांच की अवधि के दौरान मूल्य अंडरकटिंग सबसे अधिक थी।
  - देश में मांग-आपत के अंतर के बावजूद घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग, उत्पादन, घरेलू बिक्री और बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है।
  - जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि, नकद हानि हुई है और निवेश पर नकारात्मक प्रतिलाभ दर्ज किया गया है।

- ज. घरेलू उद्योग के ब्याज कवरेज अनुपात में क्षति की अवधि की तुलना में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है।
- झ. पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की माल-सूची में \*\*\*% की वृद्धि हुई है।
- ञ. मांग में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद 2020-21 और 2021-22 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान उद्योग की घरेलू बिक्री में काफी गिरावट आई है।
- ट. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है तथा घरेलू उद्योग को और अधिक वास्तविक क्षति होने का खतरा है।
- ठ. भौतिक क्षति का खतरा है क्योंकि जांच की अवधि के दौरान विषय आयात में 1.9 गुना वृद्धि हुई है, चीन में अधिशेष क्षमताएं हैं और विषय आयात की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री मूल्य और बिक्री की लागत से कम है।
- ड. घरेलू उद्योग को यह क्षति चीन जनगण से आयातों के पाटन के कारण हुई है।
62. आवेदकों ने आगे प्रस्तुत किया कि वे एक बहु-उत्पाद कंपनी हैं, विभिन्न संयंत्रों का उपयोग करके एक ही स्थान पर विभिन्न उत्पादों का निर्माण करती हैं। बिजली और भाप जैसी उपयोगिताओं को आंतरिक रूप से उत्पन्न और उपभोग किया जाता है, जो एक केंद्रीकृत संयंत्र से उत्पन्न होता है लेकिन प्रत्येक उत्पाद के संयंत्र को व्यक्तिगत रूप से आवंटित किया जाता है। प्रत्येक संयंत्र द्वारा उपयोगिता उपयोग को ट्रैक करने के लिए विस्तृत रिकॉर्ड बनाए रखा जाता है। आईपीए के विशिष्ट विनिर्माण रसायन विज्ञान के कारण, यह अन्य उत्पादों की तुलना में अधिक उपयोगिताओं का उपभोग करता है। इसलिए, घरेलू उद्योग के लिए गैर-हानिकारक मूल्य निर्धारित करते समय आईपीए उत्पादन में खपत वास्तविक उपयोगिताओं पर विचार किया जाना चाहिए।
63. आवेदक आईपीए उत्पादन के लिए प्रोपलीन का उपयोग करता है, जो अलग-अलग शुद्धता स्तरों पर विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त होता है, जो खपत दर और कीमतों को प्रभावित करता है। उच्च शुद्धता खपत को कम करती है लेकिन लागत बढ़ाती है, जबकि कम शुद्धता खपत को बढ़ाती है और कीमतों को कम करती है। प्राधिकरण को इष्टतम शुद्धता के आधार पर कच्चे माल के उपयोग का मानकीकरण करना चाहिए और गैर-हानिकारक मूल्य की विकृत गणना से बचने के लिए जांच की अवधि से मूल्य निर्धारण पर विचार करना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, प्राधिकरण क्षति की अवधि के दौरान उपयोग की जाने वाली शुद्धता के आधार पर खपत की गणना करने के लिए डेटा को समायोजित कर सकता है और तदनुसार कच्चे माल के उपयोग को मानकीकृत कर सकता है। मूल्य निर्धारण समायोजन भी आवश्यक हो सकता है। याचिकाकर्ता उनके कुशल इनपुट उपयोग की गलत आलोचना किए बिना निष्पक्ष मूल्यांकन का आग्रह करता है।
64. अन्य इच्छुक पार्टियों के तर्कों को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ट्रिब्यूनल लगातार कहता है कि 22% की वापसी गैर-हानिकारक मूल्य निर्धारित करने के लिए मानक है, जब तक कि एक अलग दर को सही ठहराने के लिए सबूत प्रस्तुत नहीं किया जाता है। ब्रिज स्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग बनाम नामित प्राधिकरण के मामले में, वैश्विक स्तर पर कम रिटर्न दिखाने वाले साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे। तथापि, इस निर्णय के बाद, ट्रिब्यूनल ने बरकरार रखा है 22% रिटर्न जब तक सम्मोहक साक्ष्य अन्यथा साबित न हो। उदाहरण के लिए, तांगशान सानो समूह हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ [2017 (349) ई. 667 (Tri. - Del.)] में, ट्रिब्यूनल ने नामित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित 22% रिटर्न की तर्कसंगतता को चुनौती देने वाले साक्ष्य के अभाव के कारण इस प्रथा को बरकरार रखा। यह माना जा सकता है कि अन्य इच्छुक पार्टियों ने इस तथ्य का कोई सबूत नहीं दिया है कि 22% पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

### ज.3 प्राधिकरण द्वारा समीक्षा

65. प्राधिकरण सभी पाटनरोधी जांचों में मानक पद्धति के रूप में नियोजित पूंजी की 22% दर (आरओसीई) को लगातार लागू करता है। ब्रिजस्टोन मामले में एलडी सीईएसटीएटी की टिप्पणियां मूल्य अंडरसेलिंग का निर्धारण करने में 22% आरओसीई के उपयोग के लिए विशिष्ट थीं, न कि गैर-हानिकारक मूल्य (एनआईपी) की गणना में इसकी उपयुक्तता। इसके अलावा, ब्रिजस्टोन निर्णय एडी नियमों के अनुलग्नक- III की शुरुआत से पहले का है, अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा इस पर निर्भरता को अनुचित प्रदान करना। बाद के मेरिनो पैनेल उत्पाद मामले में, एल. डी. सीस्टैट ने डीजीटीआर के 22% आरओसीई लागू करने के अभ्यास को बरकरार रखा।

66. विचाराधीन उत्पाद का गैर-हानिकारक मूल्य घरेलू उद्योग के संबंध में जांच की अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना और आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित किया गया है। इस उद्देश्य के लिए कंपनियों द्वारा रखे गए वित्तीय और लागत रिकॉर्ड का विस्तृत विश्लेषण/परीक्षा और सामंजस्य, जहां भी लागू हो, किया गया था।
67. शुद्धता के आधार पर कच्चे माल के उपयोग को मानकीकृत करने और गैर-हानिकारक मूल्य की विकृत गणनाओं से बचने के लिए जांच की अवधि से मूल्य निर्धारण पर विचार करने के लिए घरेलू उद्योग के अनुरोध की जांच की गई है। यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग दो स्रोतों नामत बीपीसीएल माहुल और बीपीसीएल कोच्चि से कच्चा माल (रिफाइनरी ग्रेड प्रोपलीन) प्राप्त करता है। घरेलू उद्योग का यह तर्क कि बीपीसीएल कोच्चि से खरीदे गए कच्चे माल में शुद्धता की मात्रा अधिक होती है, जिसके लिए कम मात्रा में खपत की आवश्यकता होती है, जबकि बीपीसीएल माहुल से खरीदे गए कच्चे माल में शुद्धता की निम्न मात्रा होती है, जिसके लिए अधिक मात्रा में खपत की मात्रा की आवश्यकता होती है। हालांकि, आवेदक द्वारा प्रस्तुत डेटा इसे प्रतिबिंबित नहीं करता है। यह ध्यान दिया गया है कि 2019-20 और 2020-2021 के दौरान खपत मानदंड क्रमशः \*\*\* और \*\*\* था, जहां निर्माता ने दोनों स्रोतों से कच्चे माल का उपयोग दोनों वर्षों में लगभग समान सीमा के साथ किया था। इसलिए, शुद्धता के आधार पर खपत मानदंड को मानकीकृत करने के लिए घरेलू उद्योग की दलील को तर्कसंगत नहीं पाया गया है और एनआईपी को अंतिम रूप देने के लिए इस पर विचार नहीं किया जा सकता है।
68. प्राधिकरण ने क्षति के आकलन और कारण लिंक के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न प्रस्तुतियों को नोट किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों और लागू कानूनों पर विचार करते हुए इसकी जांच की है।

### ज.3.1 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव

#### क. मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

69. वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए, भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार आकलित मांग नीचे सारणी में दी गई है।

व्यक्तियों	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	89	107	72
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	-	100	142	270
विषय देश से आयात	एमटी	78,685	52,332	35,758	72,423
अन्य देशों से आयात	एमटी	58,182	1,07,539	79,176	42,662
कुल मांग/खपत	एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	120	108	113

70. उपरोक्त के आधार पर, प्राधिकरण नोट करता है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग 2019-20 की तुलना में 2020-21 में बढ़ी है। पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में मांग में गिरावट आई और उसके बाद जांच की अवधि के दौरान फिर से वृद्धि हुई।

#### ख. विषय देश से वॉल्यूम आयात करें

71. आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकरण को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में निरपेक्ष रूप से अथवा उत्पादन अथवा खपत के सापेक्ष संबंधित देश से पाटित आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नीचे दी गई तालिका में इसका विश्लेषण किया गया है।

व्यक्तियों	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
उत्पादन					
घरेलू उद्योग	एमटी	***	***	***	***
अन्य भारतीय निर्माता	एमटी	***	***	***	***
कुल उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
अनुक्रमित	सामान्य प्रवृत्ति	100	133	164	187
कुल मांग/खपत	एमटी	***	***	***	***
अनुक्रमित	सामान्य प्रवृत्ति	100	120	108	113
विषय देश से आयात	एमटी	78,685	52,332	35,758	72,423
अन्य देशों से आयात	एमटी	58,182	1,07,539	79,176	42,662
कुल आयात	एमटी	1,36,867	1,59,870	1,14,934	1,15,084
निम्नलिखित के संबंध में आयात विषय					
उत्पादन	%	***	***	***	***
अनुक्रमित	सामान्य प्रवृत्ति	100	50	28	49
खपत	%	***	***	***	***
अनुक्रमित	सामान्य प्रवृत्ति	100	55	42	82
कुल आयात	%	57%	33%	31%	63%

72. उपरोक्त के आधार पर, प्राधिकरण नोट करता है कि:

- क. संबंधित देश से आयात की मात्रा में पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 और 2021-22 में गिरावट आई, लेकिन इसके बाद जांच की अवधि के दौरान इसमें वृद्धि हुई। 2019-20 में आयात अधिक था, जिसके कारण घरेलू उद्योग ने मात्रात्मक प्रतिबंधों के रूप में सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए एक आवेदन दायर किया था।
- ख. खपत के संबंध में आयात में पिछले वर्षों की तुलना में 2020-21 और 2021-22 में गिरावट आई है, लेकिन उसके बाद जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- ग. उत्पादन के संबंध में आयात में पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 और 2021-22 में गिरावट आई है, लेकिन उसके बाद जांच की अवधि के दौरान इसमें वृद्धि हुई है।
- घ. कुल आयात के संबंध में आयात पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में घट गया और 2020-21 की तुलना में 2021-22 में स्थिर रहा, लेकिन उसके बाद बढ़ गया। जांच की अवधि के दौरान कुल आयात के संबंध में विषय आयात सबसे अधिक था।
- ङ. जबकि पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में विषय वस्तुओं की मांग में केवल \*\*\*% की वृद्धि हुई है लेकिन संबंधित देश से आयात में \*\*\*% की वृद्धि हुई है और गैर-विषयक देशों से आयात में \*\*\*% की कमी आई है। विषय आयातों ने न केवल भारत में मांग में वृद्धि बल्कि भारत में मौजूदा मांग को भी कैप्चर किया है।

### ज.3.2 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मूल्य प्रभाव

73. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है कि क्या भारत में ऐसे उत्पादों की कीमतों की तुलना में कथित पाटित आयातों द्वारा मूल्य में काफी कमी की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा मूल्यों को कम करने अथवा मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए है। जो अन्यथा

सामान्य पाठ्यक्रम में होता। विषय देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग के मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभाव की मूल्य कम कटाई, मूल्य कम करने और मूल्य अवसाद, यदि कोई हो, के संदर्भ में जांच की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, उत्पादन लागत, निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) और घरेलू उद्योग की गैर-हानिकारक कीमत (एनआईपी) की तुलना संबंधित देश से संबंधित वस्तुओं के आयात की उतराई तक की कीमत के साथ की गई है।

#### क. मूल्य में कटौती

74. मूल्य अंडरकॉटिंग विश्लेषण के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य की तुलना संबंधित देश से आयात की उतराई तक की कीमत से की गई है। तदनुसार, संबंधित देश से डंप किए गए आयातों के कम प्रभाव निम्नानुसार हैं:

विवरण	इकाई	पीओआई
लैंडेड मूल्य	₹/एमटी	81,828
शुद्ध बिक्री प्राप्ति	₹/एमटी	***
मूल्य में कटौती	₹/एमटी	***
मूल्य में कटौती	%	***
मूल्य में कटौती	श्रेणी %	20-30

75. प्राधिकरण नोट करता है कि विषयगत आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं और मूल्य में कमी सकारात्मक और महत्वपूर्ण है। ऑनसाइट सत्यापन के दौरान, घरेलू उद्योग ने बताया कि कम आयात कीमत के बावजूद, घरेलू उद्योग विषय वस्तु की महत्वपूर्ण, निर्बाध आपूर्ति प्रदान करने की अपनी क्षमता के कारण थोड़ी अधिक कीमत बनाए रखने में सक्षम था, जो फार्मास्युटिकल में अपने ग्राहकों के लिए आवश्यक है। और रासायनिक उद्योग। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की ऊंची बिक्री कीमत के कारण आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और परिणामस्वरूप घरेलू बिक्री में गिरावट आई। इस स्थिति के परिणामस्वरूप इन्वेंट्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसके बाद उत्पादन और क्षमता उपयोग में कमी आई। परिणामस्वरूप, बढ़ती लागत के साथ आयात कीमतों में गिरावट ने जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाया।

#### ख. मूल्य दमन और अवसाद

76. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू मूल्यों को कम कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव मूल्यों को काफी हद तक कम करने या मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए है जो अन्यथा सामान्य स्थिति में होती, लागत और कीमतों में परिवर्तन की तुलना नीचे से की गई है

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
विक्रय मूल्य	₹/एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	168	156	165
बिक्री की लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	108	131	142
लैंडेड मूल्य	₹/एमटी	50,272	92,645	82,240	81,828
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	184	164	163

77. प्राधिकरण निर्धारित करता है कि:

- क. विषय देश से आयात की कीमत वर्ष 2019-20, 2021-22 और जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से कम थी।
- ख. जहां 2020-21 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में वृद्धि हुई है, वहीं इसी अवधि के दौरान लैंडेड प्राइस में गिरावट आई है।

ग. पिछले वर्ष की तुलना में, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों में उनकी बिक्री लागत में वृद्धि की तुलना में एक छोटे अंतर से वृद्धि हुई है। इस बीच, इस अवधि के दौरान विषय आयातों की लैंडेड कीमतों में कमी आई है। परिणामस्वरूप, विषयगत आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को दबा दिया है और कम कर दिया है।

### ज.3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक अनुसंधानीय

78. नियमों के अनुलग्नक II में अपेक्षा की गई है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियमों में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री में वास्तविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। लाभ, आउटपुट, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर वापसी या क्षमता का उपयोग; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, डंपिंग के मार्जिन का परिमाण; नकदी प्रवाह, सूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

### क उत्पादन, क्षमता, बिक्री और क्षमता उपयोग

79. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग निम्नलिखित तालिका में दिया गया है: -

व्यक्तियों	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
क्षमता	एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	100	100	100
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	91	108	80
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	91	108	80
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	89	107	72

80. उपरोक्त के आधार पर, प्राधिकरण निम्नलिखित नोट करता है:

- क. घरेलू उद्योग की क्षमता क्षति की अवधि के दौरान समान रही है।
- ख. पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग के उत्पादन में क्षति की अवधि की तुलना में \*\*\*% और जांच की अवधि में \*\*\*% की गिरावट आई है।
- ग. पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में क्षति की अवधि में \*\*\*% और जांच की अवधि में \*\*\*% की गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में गिरावट आई है, हालांकि भारत में मांग बढ़ी है और घरेलू उद्योग घाटे में बिक रहा है।
- घ. पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में \*\*\*% की गिरावट आई है। घरेलू उद्योग क्षति की अवधि की तुलना में जांच की अवधि के दौरान न्यूनतम क्षमता उपयोग पर कार्य कर रहा था।

### ख बाजार हिस्सेदारी

81. घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी और भारत में उत्पाद के आयात को नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है।



विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
विषय आयात	%	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	55	42	82
अन्य आयात	%	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	153	126	65
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	74	99	64
अन्य घरेलू उत्पादक	%	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	-	100	159	289
कुल	%	100%	100%	100%	100%

82. उपरोक्त के आधार पर, प्राधिकरण निम्नलिखित नोट करता है:

- क. घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी आधार वर्ष के साथ-साथ पिछले वर्ष की तुलना में कम हुई है।
- ख. अन्य घरेलू उत्पादक द्वारा उत्पादन शुरू करने के कारण 2020-21 में विषय आयात की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई। हालांकि, पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में विषय आयात की बाजार हिस्सेदारी फिर से बढ़ गई।
- ग. जबकि पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान भारत में मांग में 4% की वृद्धि हुई है, उसी अवधि के दौरान विषय आयात के बाजार हिस्से में 93% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार, विषय आयात ने मांग में वृद्धि के साथ-साथ भारत में मौजूदा मांग को भी पकड़ लिया।

### ग सूची

83. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची स्थिति नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
प्रारंभिक इन्वेंट्री	एमटी	***	***	***	***
समापन इन्वेंट्री	एमटी	***	***	***	***
औसत इन्वेंट्री	एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	60	52	170

84. उपरोक्त तालिका के आधार पर, प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग की सूची क्षति की अवधि में कई गुना बढ़ गई है। यद्यपि घरेलू उद्योग ने संबंधित वस्तुओं को घाटे में बेचा है, माल-सूची में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

### घ लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर वापसी

85. लाभप्रदता नियोजित पूंजी पर वापसी और क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के नकद लाभ नीचे तालिका में दिए गए हैं: -

व्यक्तियों	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
बिक्री की लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	108	131	142
विक्रय मूल्य	₹/एमटी	***	***	***	***

व्यक्तियों	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	168	156	165
लाभ/(हानि)	₹/एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	-100	202	-4	-26
कुल लाभ/(हानि)	₹ लाख	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	-100	181	-5	-17
नकद लाभ	₹/एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	-100	313	27	-11
पीबीआईटी	₹/एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	-100	381	17	-20
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	-100	277	20	-16

86. उपरोक्त तालिका के आधार पर, प्राधिकरण निम्नलिखित नोट करता है:

- क. वर्ष 2019-20 में भारत में आयात बढ़ा जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति लगी। घरेलू उद्योग ने इस अवधि के दौरान रक्षोपाय उपाय लागू करने के लिए आवेदन दायर किया था।
- ख. घरेलू उद्योग ने जहां 2020-21 के दौरान मुनाफा कमाया है, वहीं 2021-22 में उसे नुकसान हुआ है। इसके अलावा, पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान नुकसान में वृद्धि हुई है।
- ग. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को नकद हानि हुई है।
- घ. घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर वापसी में 2020-21 से गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल दर्ज किया है।

ड रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

87. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी नीचे तालिका में दी गई है।

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
कर्मचारियों की संख्या	सं	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	96	94	94
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/सं	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	95	114	85
प्रति दिन उत्पादकता	मीट्रिक टन/दिन	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	सं	100	91	108	80
वेतन	₹ लाख	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	136	125	78

88. उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण ने पाया है कि घरेलू उद्योग में रोजगार में क्षति की अवधि के दौरान लगातार कमी आई है, जिससे भुगतान की गई कुल मजदूरी में तदनुरूपी गिरावट आई है। इसके अलावा, उत्पादन स्तरों में कमी के कारण हानि की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादकता प्रभावित हुई है।

**च वृद्धि****89. निम्नलिखित तालिका घरेलू उद्योग के विकास मापदंडों को दर्शाती है।**

व्यक्तियों	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
क्षमता	%	-	-	-	-
उत्पादन	%	-	***	***	***
घरेलू बिक्री	%	-	***	***	***
लाभ/(हानि) प्रति यूनिट	%	-	***	***	***
प्रति यूनिट नकद लाभ	%	-	***	***	***
नियोजित पूंजी पर वापसी	%	-	***	***	***

**90. उपरोक्त के आधार पर, प्राधिकरण नोट करता है कि:**

- क. घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में 2020-21 में गिरावट आई है लेकिन 2021-22 में इसमें वृद्धि हुई है। इसके बाद, जांच की अवधि के दौरान दोनों मापदंडों में गिरावट आई।
- ख. 2020-21 में मूल्य मापदंडों में सुधार हुआ, हालांकि, 2021-22 और जांच की अवधि के दौरान इसमें गिरावट आई।
- ग. वर्ष 2020-21 के दौरान, घरेलू उद्योग नकद लाभ अर्जित करने के बावजूद लाभ में था, हालांकि, वर्ष 2021-22 के दौरान इसे नुकसान हुआ, जो POI के दौरान भी काफी बढ़ गया।
- घ. पीओआई के दौरान नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ भी ऋणात्मक था जो पिछले वर्ष की तुलना में तीव्र था।

**छ पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता**

91. प्राधिकरण नोट करता है कि पूंजीगत निवेश बढ़ाने की घरेलू उद्योग की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह इस तथ्य के कारण है कि घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में नुकसान हुआ है और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक रिटर्न दर्ज किया गया है।

**ज घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक**

92. प्राधिकरण नोट करता है कि विषय आयातों का उतराई तक का मूल्य घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य और बिक्री की लागत से कम है। इसके कारण घरेलू उद्योग को इसकी बिक्री लागत से कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर किया गया है, जिसके कारण वर्ष 2021-22 और पीओआई के दौरान नुकसान हुआ है। इस प्रकार, विषयगत आयातों ने भारत में घरेलू मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

**झ क्षति और क्षति मार्जिन की तीव्रता**

93. प्राधिकरण ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमों में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए गैर-हानिकारक मूल्य निर्धारित किए हैं। विचाराधीन उत्पाद का गैर-हानिकारक मूल्य जांच की अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना को अपनाकर निर्धारित किया गया है। घरेलू उद्योग का गैर-हानिकारक मूल्य तैयार किया गया है और क्षति माजन की गणना के लिए इसकी तुलना संबंधित देश से अवतरण मूल्य से की गई है। गैर-हानिकारक मूल्य निर्धारित करने के लिए, कच्चे माल, यूटिलिटियों और क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग करने पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन की लागत के लिए कोई असाधारण या गैर-आवर्ती खर्च नहीं लिया गया था। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (यानी, औसत शुद्ध अचल संपत्ति और औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित रिटर्न (पूर्व-कर 22%) को नियमों के अनुलग्नक III में निर्धारित गैर-हानिकारक मूल्य पर पहुंचने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी।

94. सहकारी उत्पादकों का उतराई तक का मूल्य ऐसे उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार निर्धारित किया गया है। सभी असहयोगी उत्पादकों के लिए प्राधिकरण ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अवतरण मूल्य निर्धारित किया है।

95. ऊपर निर्धारित पहुँच मूल्य और गैर-क्षतिग्रस्त मूल्य के आधार पर, उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है और उसे नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

क्र. सं.	निर्माता का नाम	गैर-हानिकारक कीमत	लैंडेड प्राइस	क्षति गुंजाइश	सीआईएफ मूल्य	क्षति गुंजाइश	क्षति गुंजाइश
		(यूएसडी/एमटी)	(यूएसडी/एमटी)	(यूएसडी/एमटी)	(यूएसडी/एमटी)	(सीआईएफ मूल्य का%)	(रेंज) %
<b>चीन पीआर</b>							
1	जुहाई लॉन्ग सक्सेस केमिकल इंडस्ट्री कं, लिमिटेड	***	***	***	***	***	0-10
2	गैर-सहयोगी/अवशिष्ट निर्यातक	***	***	***	***	***	20-30

#### ज.3.4 गैर-एट्रिब्यूशन विश्लेषण और कारण संबंध

96. इन नियमों के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों, जिनसे घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है, के अलावा किन्हीं ज्ञात कारकों की जांच की जानी अपेक्षित है ताकि इन अन्य कारकों द्वारा हुई क्षति को पाटित आयातों के कारण न ठहराया जा सके। नीचे यह जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों के अलावा अन्य कारकों के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा है।

#### क. तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत

97. प्राधिकरण नोट करता है कि कोरिया गणराज्य, ताइवान, नीदरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों से पर्याप्त मात्रा में आयात किया जाता है। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि अन्य देशों से आयात की कीमत चीन जनगण से आयात मूल्य के लिए बेंचमार्क की जाती है। प्राधिकरण ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर सभी देशों से आयातों अर्थात् चीन जनगण से आयातों की जांच की है।

व्यक्तियों	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
चीन पीआर से आयात	एमटी	78,685	52,332	35,758	72,423
वर्ष दर वर्ष परिवर्तन	%	-	-33	-32	103
कोरिया आरपी से आयात	एमटी	28,823	34,691	34,547	14,610
वर्ष दर वर्ष परिवर्तन	%	-	20	0	-58
संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात	एमटी	9,862	18,952	5,695	8,763
साल दर साल बदलाव	%	-	92	-70	54
ताइवान से आयात	एमटी	7,676	19,859	22,593	13,864
वर्ष दर वर्ष परिवर्तन	%	-	159	14	-39
नीदरलैंड से आयात	एमटी	5,162	5,033	6,440	4,177
वर्ष दर वर्ष परिवर्तन	%	-	-3	28	-35

व्यक्तियों	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
<b>उत्पादन के संबंध में आयात</b>					
चीन पीआर	%	***	***	***	***
कोरिया आरपी	%	***	***	***	***
संयुक्त राज्य अमेरिका	%	***	***	***	***
ताइवान	%	***	***	***	***
नीदरलैंड	%	***	***	***	***
<b>मांग के संबंध में आयात</b>					
चीन पीआर	%	***	***	***	***
कोरिया आरपी	%	***	***	***	***
संयुक्त राज्य अमेरिका	%	***	***	***	***
ताइवान	%	***	***	***	***
नीदरलैंड	%	***	***	***	***
<b>कुल आयात के संबंध में आयात</b>					
चीन पीआर	%	57%	33%	31%	63%
कोरिया आरपी	%	21%	22%	30%	13%
संयुक्त राज्य अमेरिका	%	7%	12%	5%	8%
ताइवान	%	6%	12%	20%	12%
नीदरलैंड	%	4%	3%	6%	4%

98. उपरोक्त के आधार पर, प्राधिकरण नोट करता है कि:

- क. जबकि पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान चीन जनगण से आयातों में 103% की वृद्धि हुई है, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर अन्य देशों से आयातों में गिरावट आई है।
- ख. जबकि पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान भारत में उत्पादन की तुलना में चीन जनगण से आयातों में वृद्धि हुई है, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर अन्य देशों से आयात में गिरावट आई है।
- ग. चीन जनगण से आयात संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात का लगभग 9 गुना था। इसके अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात भारत में मांग का केवल \*\*\*% था।
- घ. भारत में कुल आयात में चीन जन गण से आयात का बोलबाला रहा। चीन जन गण से आयात भारत में कुल आयात के आधे से अधिक था।
- ङ. चीन पीआर से आयात कोरिया आरपी से आयात का लगभग 5 गुना था और अन्य देशों की तुलना में इससे भी अधिक था।

**ख. मांग में संकुचन**

99. प्राधिकरण नोट करता है कि मांग में कोई संकुचन नहीं है क्योंकि भारत में संबंधित वस्तुओं की मांग में क्षति की अवधि में लगातार वृद्धि हुई है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को इस कारण कोई क्षति नहीं हुई है।

**ग. उपभोग का पैटर्न**

100. प्राधिकरण नोट करता है कि संबंधित वस्तुओं के उपभोग के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को नुकसान हो सकता है।

### घ. व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं और प्रतिस्पर्धा की शर्तें

101. प्राधिकरण नोट करता है कि ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं या प्रतिस्पर्धा की शर्तें नहीं हैं जिनसे घरेलू उद्योग को नुकसान हो सकता है।

### ङ. निर्यात प्रदर्शन

102. प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में अपने उत्पादन का एक छोटा हिस्सा निर्यात किया है। तथापि, ऊपर जांच की गई क्षति सूचना घरेलू बाजार के संदर्भ में केवल घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है। इस प्रकार, हुई क्षति का श्रेय घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन को नहीं दिया जा सकता।

### च. प्रौद्योगिकी का विकास

103. संबंधित वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति पहुंची है।

### छ. कंपनी के अन्य उत्पादों का प्रदर्शन

104. प्राधिकरण ने केवल विषयगत वस्तुओं के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। इसलिए, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का प्रदर्शन क्षति का संभावित कारण नहीं हो सकता है।

### झ. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

#### झ.1 अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तुतियाँ

105. उत्पादक/निर्यातक का तर्क है कि विचाराधीन उत्पाद का निर्माण करने वाले भारतीय उद्योग को सुरक्षा प्रदान करने से केवल याचिकाकर्ता के हितों की पूर्ति होगी। चीन जन गण से आयातित आइसोप्रोपिल अल्कोहल (आईपीए) पर पाटन रोधीशुल्क लगाने से जनहित के लिए गंभीर खतरा है, विशेष रूप से आईपीए पर बहुत अधिक निर्भर डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए। एकाधिकार संरचना, प्रतिस्पर्धा को दबाना और आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण में बाधा, विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ा सकती है, आर्थिक विकास और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को कम कर सकती है। जनहित पाटन रोधीशुल्क लगाने से परहेज करने का दृढ़ता से पक्षधर है, और सरकार से निष्पक्ष और सुरक्षात्मक उपायों को प्राथमिकता देने की उम्मीद है। किसी भी प्रकार की सुरक्षा अंतिम उपयोगकर्ताओं की कीमत पर घरेलू उद्योग को अनुचित लाभ प्रदान करेगी।

106. बेसिक केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स एंड डाइज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (केमक्सिल) ने निम्नलिखित प्रस्तुत किया है:

- दीपक उर्वरक और दीपक नाइट्राइट प्रत्येक की क्षमता लगभग \*\*\* मीट्रिक टन है, अर्थात् कुल मिलाकर लगभग \*\*\* मीट्रिक टन जबकि कुल भारतीय खपत लगभग \*\*\* मीट्रिक टन प्रति वर्ष है।
- आईपीए का उपयोग सभी उद्योगों, एपीआई, पेंट, रंजक आदि द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग पानी की तरह किया जाता है। चालू वर्ष के दौरान घरेलू विनिर्माताओं की सिफारिशों के आधार पर आयातों पर देश/क्षेत्रवार मात्रा प्रतिबंध लगाया गया था।
- इस कारण जो कीमत 50-70 किलो के आसपास थी, वह 100 रुपये किलो से ऊपर चली गई है। मौजूदा कीमत 150 रुपये प्रति किलोग्राम है और आगे बढ़ने की उम्मीद है। पाटन रोधी शुल्क लगाने से कीमत और बढ़ जाएगी। प्राधिकरण को पाटन रोधी शुल्क लगाने से पहले घरेलू उद्योग की लागत मूल्य, प्रक्रिया, इनपुट सॉल्वेंट्स आदि की जांच करनी चाहिए और विश्लेषण करना चाहिए कि चीन से कीमत कम क्यों है और घरेलू उद्योग उस स्तर तक क्यों नहीं पहुंच सकता है।
- असामान्य मूल्य वृद्धि के कारण, उद्योग का व्यवसाय / निर्यात नीचे चला गया है, क्योंकि हम अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं और आईपीए की असामान्य कीमत के कारण व्यवसाय खो सकते हैं।

#### झ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण

107. जनहित के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियां दी गई हैं

- पाटनरोधी शुल्क लगाने से उत्पाद के उपभोक्ताओं और आम जनता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। बल्कि, यह भारत में उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करेगा और घरेलू उद्योग के विकास में सहायता करेगा।

- ख. भारत में विषय आयात की डंपिंग के कारण घरेलू उद्योग को परिचालन बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- ग. घरेलू उद्योग का तर्क है कि कोविड-19 संकट के दौरान, चीनी आपूर्तिकर्ताओं ने अपने घरेलू बाजार पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत को आईपीए की आपूर्ति को कम करके अवसरों का फायदा उठाया। इससे वैश्विक स्तर पर और भारत में कीमतें बढ़ गईं। अब, अधिशेष क्षमता के साथ, वे घरेलू विनिर्माण को अनुचित डंपिंग प्रथाओं से बचाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए भारतीय बाजार में फिर से प्रवेश करना चाहते हैं।
- घ. चूंकि आईपीए का उपयोग फार्मास्युटिकल उत्पादों के निर्माण में किया जाता है, इसलिए भारत में संबंधित वस्तुओं के घरेलू उत्पादन को बनाए रखना आवश्यक है।
- ङ. भारत में निरंतर डंपिंग और घरेलू विनिर्माण बंद होने के मामले में, उत्पाद के उपयोगकर्ता पूरी तरह से आयात पर निर्भर होंगे।
- च. डाउनस्ट्रीम उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि आईपीए एक कच्चा माल नहीं है बल्कि केवल एक विलायक है। इस प्रकार, आईपीए के कारण डाउनस्ट्रीम उद्योग की लागत न्यूनतम है।
- छ. चूंकि नियोजित पूंजी पर प्रतिफल नकारात्मक है, इसलिए स्थिति ऐसी ही रहने की स्थिति में घरेलू उद्योग को अपना परिचालन बंद करना पड़ सकता है।
- ज. जबकि आवेदक के पास विस्तार योजनाएं हैं, भारत में पाटित आयातों की उपस्थिति के कारण यह व्यवहार्य नहीं है।
- झ. घरेलू उद्योग द्वारा संयंत्र बंद किए जाने की स्थिति में, देश में मांग-आपूत का अंतर बढ़ने की संभावना है।
- ञ. पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में आयात प्रतिबंधित नहीं होता है। किसी भी मामले में, चूंकि भारत में मात्रात्मक प्रतिबंध लागू होने के बावजूद मांग-आपूत में कोई अंतर नहीं था, इसलिए पाटनरोधी शुल्क लगाने से मांग-आपूत में अंतर नहीं होगा।
- ट. आयात के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध हैं जो भारत में मांग-आपूर्ति के अंतर को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। ऐतिहासिक रूप से, अन्य देशों से भारत में आयात अधिक था और केवल चीन से डंपिंग के कारण कम हुआ है।
- ठ. पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में एकाधिकार नहीं होगा क्योंकि भारत में संबंधित वस्तुओं के दो उत्पादक हैं और उत्पाद का आयात संबंधित देश के अलावा विभिन्न स्रोतों से किया जा रहा है।

## झ.2 प्राधिकरण द्वारा समीक्षा

108. प्राधिकरण मानता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से पाटनरोधी पद्धतियों से प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होगा, घरेलू उद्योग की गिरावट को रोका जा सकेगा और संबंधित वस्तुओं के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में सहायता मिलेगी। सामान्यतः पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके जो देश के सामान्य हित में है। अतः पाटनरोधी शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। प्राधिकरण नोट करता है कि पाटन रोधीशुल्क लगाने से संबंधित देश से आयात किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं होगा, और इसलिए, उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।
109. पाटन रोधीशुल्क लगाने से भारत में आयात प्रतिबंधित नहीं होता है बल्कि केवल यह सुनिश्चित होता है कि आयात उचित मूल्य पर हो। रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, भारत में विषयगत वस्तुओं की कोई कमी नहीं होगी क्योंकि मांग-आपूत के अंतर को संबंधित देश से इतर स्रोतों से आयात के माध्यम से पूरा किया जा सकता है, भले ही संबंधित देश से कोई आयात न हो।

विवरण	मात्रा (मीट्रिक टन)
आवेदक की क्षमता	***
अन्य घरेलू उत्पादक की क्षमता	***
भारत में औसत मांग*	***
मांग-आपूर्ति अंतर	***
अन्य स्रोतों से आयात**	***

\*2019-20 से 2021-22 में मांग के आधार पर

\*\* क्षति की अवधि के दौरान प्रत्येक देश से आयात की उच्चतम मात्रा

110. आगे यह देखा गया है कि भारत में एक से अधिक उत्पादक हैं और संबंधित देश के अलावा अन्य देशों से पर्याप्त आयात किए जाते हैं। इस प्रकार, किसी एक देश से आयात पर पाटन रोधीशुल्क लगाने से भारत में एकाधिकार की स्थिति नहीं बनेगी।

111. अतः प्राधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से आम जनता अथवा डाउनस्ट्रीम उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ज. गैर-हानिकारक मूल्य के निर्धारण के लिए पद्धति

112. विचाराधीन उत्पाद की गैर-हानिकारक कीमत घरेलू उद्योग के संबंध में जांच की अवधि (अप्रैल 2022 से मार्च 2023) के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित जानकारी और डेटा को अपनाकर निर्धारित की गई है। इस उद्देश्य के लिए कंपनियों द्वारा रखे गए वित्तीय और लागत रिकार्डों का विस्तृत विश्लेषण/जांच, जहां भी लागू हो, की गई थी। घरेलू उद्योग के लिए गैर-हानिकारक मूल्य नियमों के अनुबंध-III में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित किए गए हैं जैसा कि संक्षेप में नीचे वर्णित है:

क. कच्चे माल की लागत: जांच की अवधि और पूर्ववर्ती तीन वर्षों की अवधि में, जांच की अवधि में प्रचलित दरों पर घरेलू उत्पादक द्वारा कच्चे माल का सर्वोत्तम उपयोग माना गया था।

ख. उपयोगिताओं की लागत जांच की अवधि और पूर्ववर्ती तीन वर्षों की अवधि के दौरान घरेलू उत्पादक द्वारा जांच की अवधि में प्रचलित दरों पर उपयोगिताओं के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया था।

ग. उत्पादन: जांच की अवधि और पिछले तीन वर्षों की अवधि में उत्पादन क्षमता का सबसे अच्छा उपयोग माना जाता था।

घ. वेतन और मजदूरी: इस शीर्ष के तहत समूहीकृत और उत्पादन लागत पर लगाए गए खर्चों के औचित्य की जांच की गई। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन लागत पर कोई असाधारण अथवा अनावर्ती व्यय प्रभारित न किया जाए।

ङ. "सा : उत्पादन लागत पर प्रभारित मूल्यहास की राशि की तर्कसंगतता की जांच की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संबंधित वस्तुओं के उत्पादन पर तैनात नहीं की गई सुविधाओं के लिए कोई शुल्क नहीं लगाया गया है।

च. व्ययों की पहचान और आबंटन/विभाजन: जांच की अवधि के लिए दावा किए गए विभिन्न खर्चों की औचित्य और औचित्य की जांच और जांच तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष में संबंधित राशियों के साथ तुलना करके की गई है और गैर-हानिकारक मूल्य की गणना के लिए स्वीकार किया गया है।

छ. नियोजित पूंजी पर उचित रिटर्न: ब्याज, कॉर्पोरेट कर और लाभ की वसूली के लिए विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (यानी औसत शुद्ध स्थिर संपत्ति और औसत कार्यशील पूंजी) पर 22% पर एक उचित रिटर्न (पूर्व-कर) की अनुमति दी गई थी।

ज. ब्याज: ब्याज को बिक्री की लागत के एक मद के रूप में अनुमति दी जाती है और ब्याज में कटौती करने के बाद, वापसी की शेष राशि को गैर-हानिकारक मूल्य पर पहुंचने के लिए पूर्व-कर लाभ के रूप में अनुमति दी गई है।

झ. घरेलू उद्योग के लिए गैर-हानिकारक मूल्य: विचाराधीन उत्पाद के लिए एनआईपी \*\*\* ₹/MT है।

ट. पोस्ट प्रकटीकरण टिप्पणियाँ

ट.1 अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तुतियाँ

113. याचिकाकर्ता द्वारा कोरिया आरपी को इस जांच में विषय देशों से बाहर रखना प्राधिकरण को गुमराह करने का एक प्रयास है, जो जांच की अखंडता और निष्पक्षता के बारे में गंभीर चिंता पैदा करता है। दीपक फर्टिलाइजर ने जांच की अवधि के दौरान कोरिया से 7.14 मिलियन डॉलर मूल्य की विषय वस्तुओं का आयात किया, जो कोरियाई उत्पादकों के साथ महत्वपूर्ण व्यापार संबंधों का संकेत देता है। हमारा मानना है कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर कोरिया आरपी को छोड़ दिया ताकि दीपक फर्टिलाइजर को जांच के परिणाम को प्रभावित करते हुए अधिक अनुकूल परिस्थितियों में माल आयात जारी रखने की अनुमति मिल सके। प्राधिकरण से अनुरोध है कि वह अपने अंतिम निष्कर्षों में इस मुद्दे की पूरी तरह से समीक्षा करे।



114. उत्पादक/निर्यातक का तर्क है कि प्राधिकरण का महीने-दर-महीने विश्लेषण त्रुटिपूर्ण है क्योंकि इसने जांच अवधि के दौरान क्षति और पाटन मार्जिनका लगातार विश्लेषण नहीं किया। विशिष्ट महीनों के दौरान ताइवान, कोरिया, अमेरिका और नीदरलैंड से आयात मूल्य अक्सर चीन की तुलना में कम थे। इसलिए, बाजार मूल्य में कटौती को केवल कम कीमत वाले चीनी आयात के लिए जिम्मेदार ठहराना गलत है। अन्य देशों से आयात भी मूल्य बेंचमार्क को प्रभावित करता है, जिससे चीनी कीमतों में और कटौती होती है। जांच में उन सभी देशों को शामिल किया जाना चाहिए था जिनके आयात मूल्य चीन से काफी मेल खाते हैं।
115. निर्यातक का दावा है कि पाटन रोधीजांच में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून गैर-भेदभाव और निष्पक्षता पर जोर देते हैं। दूसरों द्वारा समान प्रथाओं पर विचार किए बिना एक देश को लक्षित करना इन मानदंडों का उल्लंघन करता है। डंपिंग रोधी उपायों का उद्देश्य घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुंचाने वाले अनुचित व्यापार व्यवहारों से निपटना है। वैश्विक व्यापार समझौतों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए लगाए गए किसी भी शुल्क को सही ठहराने के लिए सभी निर्यातक देशों में एक व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। केवल चीन पर ध्यान केंद्रित करना, जबकि अन्य देशों से तुलनीय प्रथाओं की उपेक्षा करना, व्यापक मूल्य अंडरकटिंग और उद्योग की क्षति को संबोधित करने में मनमाना और अप्रभावी माना जा सकता है।

## ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण

116. आवेदक का तर्क है कि प्राधिकरण का प्रस्तावित निष्कर्ष - 2020-21 में बढ़ती मांग और उस वर्ष के दौरान आयात में गिरावट को उजागर करना - त्रुटिपूर्ण है। उनका तर्क है कि 2019-20 और 2020-21 क्षति विश्लेषण के लिए अनुपयुक्त हैं क्योंकि 2019-20 में घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाने वाले आयात में वृद्धि देखी गई, और 2020-21 कोविड-19 महामारी से बाधित हुआ, जिसके कारण असामान्य मांग और चीनी उत्पादकों द्वारा आयात में कमी आई। आवेदक का दावा है कि केवल वर्ष 2021-22 का उपयोग मांग, आयात में परिवर्तन और घरेलू उद्योग को नुकसान के मूल्यांकन के लिए किया जाना चाहिए। वे इस बात पर भी जोर देते हैं कि व्यापक विश्लेषण के लिए चार साल की अवधि में क्षति का आकलन करना महत्वपूर्ण है, और केवल आधार वर्ष की तुलना जांच अवधि से करना उद्देश्यहीन होगा। उपरोक्त के प्रकाश में, आवेदक का तर्क है कि घरेलू उद्योग की आर्थिक स्थिति का आकलन क्षति की अवधि के दौरान की घटनाओं पर विचार करके किया जाना चाहिए, न कि केवल अंत-बिंदु से अंत-बिंदु विश्लेषण पर निर्भर रहने के।
117. प्राधिकरण ने नोट किया है कि हालांकि 3% से अधिक व्यक्तिगत आयात हिस्सेदारी वाले सभी देशों के खिलाफ जांच शुरू करना और नुकसान का संचयी मूल्यांकन करना मानक प्रथा है, लेकिन वर्तमान मामले में ऐसा नहीं किया गया था। पिछली जांच, जैसे कि डेकोर पेपर, विनाइल टाइल्स, क्लोरीनयुक्त पॉलीविनाइल क्लोराइड, अखबारी कागज, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन और पीवीसी पेस्ट राल में, ने महत्वपूर्ण आयात वाले देशों को बाहर रखा है, यह सुझाव देते हुए कि ऐसे सभी देशों को शामिल करने का अभ्यास लगातार लागू नहीं होता है।
118. आवेदक का तर्क है कि गैर-हानिकारक मूल्य निर्धारित करने के लिए घरेलू उद्योग को अनुमत निवेश पर प्रतिलाभ 2.41% पर अपर्याप्त है। अपने संयंत्र और मशीनरी के मूल्यहास के बावजूद, वे तर्क देते हैं कि घरेलू उद्योग एक उचित लाभ का हकदार है। इसके अतिरिक्त, निर्मित सामान्य मूल्य की गणना के लिए प्राधिकरण द्वारा दिए गए 5% लाभ मार्जिन के परिणामस्वरूप डंपिंग में लगे विदेशी उत्पादकों की तुलना में घरेलू उद्योग के लिए काफी कम लाभ होता है।
119. आमतौर पर सहयोग नहीं करने वाले निर्यातकों को असहयोग को हतोत्साहित करने के लिए वैश्विक स्तर पर अधिक शुल्क का सामना करना पड़ता है। हालांकि, इस मामले में, यदि शुल्क उनके निर्यात मूल्य के आधार पर निर्धारित किए जाने वाले तुलनीय निर्धारित किए जाते हैं, तो यह भविष्य में असहयोग को प्रोत्साहित कर सकता है। इसलिए, प्राधिकरण से सहयोग के लिए प्रोत्साहन बनाए रखने के लिए गैर-सहयोगी निर्यातकों पर उच्च शुल्क लगाने का आग्रह किया जाता है।

**ट.3 प्राधिकरण द्वारा समीक्षा**

120. प्राधिकरण ने इच्छुक पाटयों द्वारा किए गए प्रकटीकरण पश्चात प्रस्तुतियों की जांच की है और यह नोट किया है कि अधिकांश टिप्पणियां/प्रस्तुतियां पुनरावृत्ति हैं जिनकी पहले ही उपयुक्त रूप से जांच की जा चुकी है और अंतिम निष्कर्षों के संगत अनुच्छेद में पर्याप्त रूप से समाधान किया जा चुका है। संक्षिप्तता की दृष्टि से प्राधिकरण द्वारा प्रकटीकरण के बाद की जांच में भी इसे दोहराया नहीं जा रहा है। इच्छुक पक्षों द्वारा प्रकटीकरण पश्चात टिप्पणियों/प्रस्तुतियों में पहली बार उठाए गए मुद्दों और प्राधिकरण द्वारा प्रासंगिक समझे गए मुद्दों की नीचे जांच की जाती है।
121. इच्छुक पार्टी का यह दावा कि आवेदक द्वारा कोरिया आरपी को जांच से बाहर रखना प्राधिकरण को गुमराह करने का प्रयास है, डीजी सिस्टम्स के डेटा द्वारा समर्थित नहीं है। समीक्षा के बाद, प्राधिकरण ने सत्यापित किया कि दीपक फर्टिलाइजर्स ने कोरिया से 4,476 मीट्रिक टन विषय वस्तुओं का आयात किया, जिसकी कीमत 4.47 मिलियन डॉलर थी। ये आयात कुल आयात का 3.93% और जांच की अवधि के दौरान कुल मांग का 2.01% है। यह डेटा इंगित करता है कि कोरिया आरपी से आयात की मात्रा और मूल्य समग्र बाजार के संदर्भ में अपेक्षाकृत मामूली हैं, इस दावे को कम करते हुए कि बहिष्करण का उद्देश्य जांच के परिणाम को प्रभावित करना था।
122. इच्छुक पार्टी ने तर्क दिया कि प्राधिकरण का महीने-दर-महीने विश्लेषण क्षति और पाटन मार्जिनकी असंगत परीक्षा के कारण त्रुटिपूर्ण है, इस संबंध में प्राधिकरण नोट करता है कि उसने एक विस्तृत मासिक विश्लेषण किया है और चीनी आयात और ताइवान, कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और नीदरलैंड के बीच भारतित औसत मूल्य अंतर की गणना की है। इस विश्लेषण से पता चला कि इन देशों से आयात की तुलना में चीनी आयात कीमत में कम थे, जिससे समग्र बाजार कीमतों पर महत्वपूर्ण दबाव पड़ा।
123. इसके अलावा, जांच की अवधि के दौरान लगभग 37,000 मीट्रिक टन चीनी आयात में उल्लेखनीय वृद्धि, अन्य प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं से आयात में 31,000 मीट्रिक टन की गिरावट के साथ, बाजार पर चीनी मूल्य निर्धारण के पर्याप्त प्रभाव को प्रदर्शित करता है। प्राधिकरण के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि चीनी आयात की कम कीमतों ने न केवल प्रतिस्पर्धियों को कम कर दिया, बल्कि उनके बाजार हिस्सेदारी और मात्रा में भी कमी आई। इस प्रकार, महीने-दर-महीने विश्लेषण प्रभावी रूप से बाजार मूल्य में कटौती को चलाने और घरेलू उद्योग को भौतिक नुकसान पहुंचाने में चीनी आयात की भूमिका पर प्रकाश डालता है, जिससे प्राधिकरण के विश्लेषण की उपयुक्तता को मजबूत किया जाता है।
124. आवेदक का तर्क है कि मांग विश्लेषण के लिए प्राधिकरण द्वारा 2019-20 और 2020-21 के डेटा का उपयोग त्रुटिपूर्ण है क्योंकि 2019-20 में उच्च आयात स्तर था और 2020-21 कोविड-19 द्वारा बाधित था। हालांकि, पूरी तस्वीर को समझने के लिए कई वर्षों में मांग को देखना महत्वपूर्ण है। इन वर्षों के आंकड़ों को शामिल करने से यह देखने में मदद मिलती है कि समय के साथ मांग और आयात कैसे बदल गए हैं और घरेलू उद्योग पर उनका समग्र प्रभाव कैसे बदल गया है। केवल वर्ष 2021-22 पर भरोसा करने से पूरा दृष्टिकोण नहीं मिल सकता है। पूर्ण क्षति अवधि पर विचार करके, प्राधिकरण एक स्पष्ट और अधिक सटीक मूल्यांकन प्रदान करता है कि मांग और आयात में परिवर्तन ने उद्योग को कैसे प्रभावित किया है।
125. आवेदक द्वारा किए गए दावे के जवाब में कि महत्वपूर्ण आयात वाले सभी देशों को शामिल करना प्राधिकरण की मानक प्रथा नहीं है, प्राधिकरण नोट करता है कि प्रत्येक एंटी-डॉपिंग जांच को संबोधित करने के लिए इसके विशिष्ट संदर्भ पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है। प्रत्येक मामले के अनूठे पहलू। वर्तमान जांच में, अन्य देशों से आयात 3% से अधिक होने के बावजूद, प्राधिकरण ने पाया है कि चीनी निर्यातकों और उत्पादकों का बाजार पर पर्याप्त नियंत्रण है, जिससे अन्य देशों से आयात में गिरावट आई है। नतीजतन, यह निष्कर्ष निकाला गया कि घरेलू उद्योग को हुए नुकसान से निपटने के लिए केवल चीन पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त है। इसलिए, प्राधिकरण ने महत्वपूर्ण आयात वाले अन्य सभी देशों के खिलाफ जांच शुरू नहीं की है।
126. निवेश पर प्रतिफल की गणना के संबंध में चिंताओं के संबंध में प्राधिकरण नोट करता है कि आरओआई की गणना पाटन रोधीनियम, 1995 के अनुलग्नक III में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार की गई है, और यह घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर आधारित है।
127. प्राधिकरण नोट करता है कि वर्तमान एंटी-डॉपिंग जांच में अवशिष्ट निर्यातकों के लिए गणना की गई डॉपिंग और क्षति मार्जिन डीजी सिस्टम डेटा से ली गई है और भाग लेने वाले निर्यातकों के लिए गणना की गई मार्जिन गैर-भागीदारी

निर्यातकों के लिए गणना किए गए मार्जिन से कम है। इसके अलावा, ये उच्च मार्जिन गैर-भागीदारी वाले निर्यातकों द्वारा असहयोग के लिए आवश्यक और आनुपातिक प्रतिक्रिया को दर्शाते हैं।

#### ठ. निष्कर्ष

128. किए गए प्रस्तुतीकरण, इच्छुक पक्षों द्वारा प्रदान की गई प्रमाणित जानकारी और प्राधिकरण के समक्ष उपलब्ध तथ्यों के आधार पर, जैसा कि उपरोक्त अनुच्छेदग्राफ में दर्ज और जांच की गई है, और डंपिंग के निर्धारण और घरेलू उद्योग को परिणामी नुकसान के आधार पर, प्राधिकरण निम्नलिखित निष्कर्ष निकालता है:

- I. **विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु** : घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तु और संबंधित देशों से निर्यात की जाने वाली विषय वस्तुएं एडी नियम, 1995 के नियम 2 (डी) के संदर्भ में एक दूसरे के लिए 'वस्तु की तरह' हैं।
- II. **घरेलू उद्योग की स्थिति**: आवेदक पात्र घरेलू उत्पादन का 100% हिस्सा है। आवेदक विज्ञापन नियम, 1995 के नियम 2 (बी) के तहत निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करता है और आवेदन एडी नियम, 1995 के नियम 5 (3) के तहत स्थायी आवश्यकताओं को पूरा करता है।
- III. आवेदन में पाटन रोधी जांच शुरू करने के प्रयोजन के लिए सभी प्रासंगिक सूचनाएं तथा पाटन रोधी नियम, 1995 के नियम 5(2) के अनुसार आवश्यक साक्ष्य शामिल थे, ताकि पाटन रोधी नियम, 1995 के नियम 5(3) के अनुसार घरेलू उद्योग को डंपिंग और भौतिक क्षति के निर्धारण के लिए वर्तमान जांच शुरू करने को उचित ठहराया जा सके।
- IV. **डंपिंग**: चीन जनगण के एक उत्पादक नामत झुहाई लांग सक्सेस केमिकल इंडस्ट्री कं, लि ने जांच में भाग लिया। ऐसे निर्यातक द्वारा प्रदान की गई जानकारी और निर्मित सामान्य मूल्य के आधार पर, झुहाई लांग सक्सेस केमिकल इंडस्ट्री कं, लिमिटेड के निर्यात के लिए पाटन मार्जिनसकारात्मक होने के लिए निर्धारित किया गया था।
- V. **मात्रा प्रभाव**: आयात की मात्रा और विषय देश से वस्तु का पाटन मार्जिन AD नियम, 1995 के अनुलग्नक – II के अनुच्छेद (iii) के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से ऊपर पाया गया।
- VI. घरेलू उद्योग की स्थिति पर पाटित किए गए आयात के मात्रा प्रभाव के संबंध में, यह पाया गया कि इस तरह के आयात भारत में पीयूसी के उत्पादन और खपत के सापेक्ष और साथ ही साथ पूर्ण रूप से बढ़े हैं। आगे यह पाया गया कि मांग में वृद्धि लगभग पूरी तरह से ऐसे पाटित आयातों द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी।
- VII. **मूल्य प्रभाव**: इस तरह के डंप किए गए आयातों के मूल्य प्रभाव के संबंध में, यह पाया गया कि संबंधित देश से मूल्य कम करना सकारात्मक था। आगे यह पाया गया कि इस प्रकार के पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे थे।
- VIII. **घरेलू उद्योग के वॉल्यूमेट्रिक और वित्तीय अनुच्छेदमीटर**: जहां तक घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर ऐसे डंप किए गए आयातों के प्रभाव का संबंध है, निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे:
  - क. **उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, बिक्री और बाजार हिस्सेदारी**: आवेदक की क्षमता स्थिर बनी हुई है। हालांकि, डंप किए गए आयात की उपस्थिति के कारण यह अपनी क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम नहीं था। क्षति की अवधि की तुलना में पीओआई में आवेदक के उत्पादन के साथ-साथ बिक्री में गिरावट आई। मांग में काफी वृद्धि हुई थी जिसे बड़े पैमाने पर डंप किए गए आयात द्वारा पूरा किया गया था।
  - ख. **बिक्री की लागत, बिक्री मूल्य, लाभप्रदता, और नियोजित पूंजी पर वापसी**: चोट की अवधि के दौरान आवेदक की प्रति इकाई बिक्री लागत में वृद्धि हुई है। आवेदक का विक्रय मूल्य वर्ष 2020-21 को छोड़कर बिक्री की लागत से कम रहा है। आवेदक के नकद लाभ, ब्याज और कर से पहले लाभ, साथ ही नियोजित पूंजी पर रिटर्न में पिछले वर्ष की तुलना में काफी गिरावट आई है।
  - ग. **इन्वेंटरी**: आवेदक की औसत इन्वेंटरी में जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई।
  - घ. **कर्मचारियों की संख्या, उत्पादकता और मजदूरी**: क्षति की अवधि में कर्मचारियों की संख्या में गिरावट आई है। पीओआई में उन्हें भुगतान की जाने वाली मजदूरी में भी गिरावट आई है। तथापि,

पाटित आयातों के परिणामस्वरूप उत्पादन में गिरावट के कारण आवेदक की उत्पादकता प्रभावित हुई है।

ड. विकास: उत्पादन, घरेलू बिक्री, लाभ और नियोजित पूंजी पर वापसी के संदर्भ में आवेदक की वृद्धि डंप किए गए आयात से प्रतिकूल रूप से प्रभावित पाई गई।

च. पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता: यह पाया गया कि संबंधित वस्तुओं की मांग में वृद्धि के बावजूद, आवेदक का प्रदर्शन खराब हो गया था जिसने पूंजीगत निवेश जुटाने की इसकी क्षमता को प्रभावित किया है।

x. कारण लिंक यह पाया गया कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है और क्षति का कोई अन्य ज्ञात कारक नहीं पाया गया। पीओआई के दौरान पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है जिसके कारण घरेलू उद्योग की माल-सूची में वृद्धि हुई है। भारतीय बाजार में पाटित आयातों की उपस्थिति ने आवेदक को अपनी बिक्री लागत से कम कीमतों पर अपनी समान वस्तु बेचने के लिए बाध्य किया, जिससे घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मानदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

xi. क्षति मार्जिन: एडी नियम, 1995 के अनुलग्नक - III के अनुसार निर्धारित गैर-हानिकारक मूल्य और एडी नियमों के नियम 17 (3) (बी) के तहत आवश्यक विषय देशों से विषय आयात के उतरा मूल्य की तुलना करने पर, चीन जन गण से निर्माता के लिए क्षति मार्जिन, अर्थात् झुहाई लॉन्ग सक्सेस केमिकल इंडस्ट्री कं, (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और

भारतीय उद्योग के मुद्दे: इच्छुक पार्टियों में से किसी ने भी कोई ठोस मात्रात्मक डेटा दायर नहीं किया जिसके माध्यम से अंतिम उपयोगकर्ता पर पाटन रोधीकर्तव्यों के प्रभाव का आकलन किया जा सके। यह नोट किया गया है कि यदि व्यवहार्य घरेलू उद्योग मौजूद है तो पीयूसी के उपयोगकर्ताओं के पास विकल्प होंगे।

#### ड. सिफारिशें

129. प्राधिकरण नोट करता है कि जांच शुरू की गई थी और चीन सरकार पीआर सहित सभी इच्छुक पक्षों को अधिसूचित किया गया था और उन्हें डंपिंग, क्षति, कारण लिंक और उपायों के प्रभाव के पहलू पर जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था, यदि सिफारिश की गई थी। पाटनरोधी शुल्क नियमावली के अंतर्गत यथा निर्धारित जांच के उपबंधों के अनुसार जांच शुरू करने और संचालित करने के पश्चात् प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि संबंधित वस्तुओं पर शुल्क लगाया जाना अपेक्षित है।

130. इसके अलावा, एडी नियम, 1995 के नियम 17 (1) (ख) में प्रतिपादित कम शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण डंपिंग के मार्जिन या क्षति के मार्जिन के कम के बराबर निश्चित पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है, ताकि घरेलू उद्योग को नुकसान को दूर किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकरण चीन जनगण में उद्भूत अथवा चीन से निर्यातित संबंधित वस्तुओं के आयात पर केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए ऐसे संशोधित निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है, जैसा कि नीचे दी गई शुल्क सारणी के कॉलम 7 में दर्शाया गया है।

#### शुल्क तालिका

क्र.सं.	एच एस कोड	माल का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	निर्माता	कर (\$/एमटी)
1	2	3	4	5	6	7
1.	29051220#	आइसोप्रोपिल अल्कोहल	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	झुहाई लॉन्ग सक्सेस केमिकल इंडस्ट्री कं, लिमिटेड	82
2.	-वही-	आइसोप्रोपिल अल्कोहल	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. के अलावा कोई भी देश	कोई भी निर्माता	217

क्र.सं.	एच एस कोड	माल का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	निर्माता	कर (\$/एमटी)
3.	-वही-	आइसोप्रोपिल अल्कोहल	चीन जन. गण. के अलावा कोई भी देश	चीन जन. गण.	कोई भी निर्माता	217

# सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

131. इस अंतिम निष्कर्ष से उत्पन्न पदनामित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील की जाएगी।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

New Delhi, the 14th August, 2024

**FINAL FINDINGS**

**Case No. AD(OI) – 09/2023**

**Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of "Isopropyl Alcohol" originating in or exported from China PR.**

**F. No. 6/09/2023-DGTR:-** Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter referred as the 'AD Rules' or the 'Anti-dumping Rules' or the 'Rules');

**A. BACKGROUND OF THE CASE**

1. Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Limited (hereinafter also referred to as the "applicant") filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority"), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Rules" or "Anti-Dumping Rules"), for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of "Isopropyl Alcohol" (hereinafter also referred to as the "product under consideration" or "subject goods" or "IPA"), originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the "subject country").
2. The Authority, on the basis of *prima facie* evidence submitted by the applicant, issued a public notice vide Notification No. 6/09/2023-DGTR dated 29<sup>th</sup> September 2023, published in the Gazette of India Extraordinary, initiated the subject investigation in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

**B. PROCEDURE**

3. The procedure described herein below has been followed with regard to the subject investigation:
  - i. The Authority notified the embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 supra.
  - ii. The Authority issued a public notice dated 29<sup>th</sup> September 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject country.
  - iii. The Authority sent a copy of the initiation notification along with questionnaires to the embassy of the subject country in India, known producers/exporters from the subject country, known

- importers/users and the domestic industry as well as other domestic producers as per the email addresses made available by the applicant and requested them to make their views known, in writing, within the prescribed time limit.
- iv. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the embassy of the subject country in India, the known producers/exporters, importers and users in accordance with Rule 6(3) of the Rules.
- v. The embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from its country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.
- vi. The Authority sent exporter's questionnaires to the following known producers/exporters in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
1. Avantor Performance Materials
  2. Chang Chun Chemical (Panjin)
  3. Dezhou Detian Chemical
  4. Hubei Kelin Bolun New Materials Co.
  5. Mitsui Chemicals
  6. Petrochina Jinzhou PC
  7. Shandong Dadi Supu Chemical
  8. Yancheng Super Chemical Technology
  9. Zhejiang Xinhua Chemical Co., Ltd.
  10. Zibo Nalcohol Chemical Co.
  11. Hi-Tech Spring Chemical Co.
  12. Zhuhai Long Success Chemical Industry Co., Ltd.
- vii. The following producers / exporters filed response to the exporters' questionnaire issued by the Authority.
1. Zhuhai Long Success Chemical Industry Co., Ltd.
  2. Fox Chem PTE Limited
  3. SK Chemical Trading (HK) Limited
- viii. The Authority sent Importer's Questionnaire to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
1. Adama India Private Limited
  2. Ami Riddhi Chem Private Limited
  3. Archoma India Private Limited
  4. Arkema Peroxides India Private Limited
  5. Aspen International Private Limited
  6. Aurigene Discovery Technologies Limited
  7. Aurobindo Pharma Limited
  8. Bharat Jyoti Impex
  9. Biocon Limited
  10. Brenntag Ingredients (India) Private Limited
  11. C J Shah and Co.
  12. Chemi Tech Engineers Private Limited

13. Chemical Corp Private Limited
14. Flora Chemicals
15. Hazel Mercantile Limited
16. Insecticides India Limited
17. K. Uttamlal & Company
18. Khushbu Dye Chem Private Limited
19. KLJ Resources Limited
20. L J. International Limited
21. Laurus Labs Limited
22. Lok Chemicals Private Limited
23. Lupin Limited
24. Maharashtra Chemical Products
25. Mayur Chemicals
26. Micro Labs Limited
27. Mylan Laboratories Limited
28. Nikeon Corporation
29. Overseas Polymers Private Limited
30. R.R. Innovative Private Limited
31. Reliance Organic
32. Sanjay Chemicals (India) Private Limited
33. Samman Trade Impex
34. Saraca Laboratories Limited
35. Satya Deeptha Pharmaceuticals Limited
36. Shree Bankey Behari Lal Board Mills
37. Signet Chemical Corporation Private Limited
38. Symrise Private Limited
39. T.M. Thakore Pharmaceutical Laboratories
40. Technova Imaging Systems Private Limited
41. Teva API India Private Limited
42. Trident Chemphar Limited
43. Urmi Chemicals
44. V.D.H. Organics Private Limited
45. Vertex Chemicals
46. Vivimed Labs Limited
47. Yasho Industries Private Limited
48. ZCL Chemicals Limited
49. Ramniklal
50. Pioneer Chemicals
51. Shivtex
52. Ujjin Pharma

53. Jupiter Dye Chem
  54. Pon Pure Chemicals India Private Limited
- ix. None of the importers/users have participated in the present investigation by filing a response to the importers' / users' questionnaires issued by the Authority.
  - x. The Authority issued economic interest questionnaire to all interested parties and concerned ministry. The following parties have filed a response to the economic interest questionnaire.
    1. Domestic industry
    2. Zhuhai Long Success Chemical Industry Co., Ltd.
  - xi. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
  - xii. The interested parties were asked vide notification dated 21<sup>st</sup> February 2024 to share the non-confidential version of the responses, submissions and evidence presented by them with the other interested parties.
  - xiii. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was duly received by the Authority. The Authority has relied upon the DG Systems data for the purpose of computation of the volume of imports.
  - xiv. The Non-Injurious Price (NIP) has been determined based on the cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry, maintained as per Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), has been worked out so as to ascertain whether the present interim anti-dumping duty would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
  - xv. The period of investigation for the purpose of the present anti-dumping investigation is from 1<sup>st</sup> April 2022 to 31<sup>st</sup> March 2023 (12 Months). The injury investigation period has been considered as the period from 1<sup>st</sup> April 2019 - 31<sup>st</sup> March 2020, 1<sup>st</sup> April 2020 - 31<sup>st</sup> March 2021, 1<sup>st</sup> April 2021 – 31<sup>st</sup> March 2022, and the period of investigation.
  - xvi. The Authority sought further information from the other interested parties to the extent deemed necessary. The verification of the data provided by the other interested parties was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation. The Authority has considered the verified data of the interested parties in its analysis in the present case.
  - xvii. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 26<sup>th</sup> June, 2024. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
  - xviii. The submissions made by the interested parties, arguments raised and information provided by various interested parties during the course of investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority in the present final findings.
  - xix. The Authority, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of the present final findings to the extent possible and verified the data/ documents submitted by the domestic industry to the extent considered relevant, practicable and necessary.
  - xx. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.



- xxi. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority considered such interested parties as non-cooperative and recorded the present final findings on the basis of the facts available.
- xxii. '\*\*\*' in the present final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xxiii. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is **1USD = ₹ 81.06**

## C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

### C.1 Submissions by the other interested parties

4. No submissions have been made by the other interested parties with regard to the scope of product under consideration or like article.

### C.2 Submissions by the domestic industry

5. The submissions made by the domestic industry with regard to the scope of product under consideration and like article are as follows:
- i. The product under consideration is Isopropyl Alcohol (IPA) also known as Isopropanol.
  - ii. IPA can either be manufactured using propylene as a raw material or acetone as raw material.
  - iii. IPA is a colorless, flammable liquid with a strong odor and used to manufacture a wide variety of industrial and household chemicals. IPA is also used for major applications in the production of bulk drugs and drug formulations which are vital in the pharmaceutical manufacturing.
  - iv. It is also used as a common ingredient in chemicals such as antiseptics, disinfectants, and detergents.
  - v. The product under consideration consists of 99.8% IPA, 0.1% water and residual impurities.
  - vi. The product manufactured by the domestic industry is commercially and technically substitutable and is being used by the consumers interchangeably. Thus, product produced by domestic industry is like article to the product imported from the subject country.

### C.3 Examination of the Authority

6. The product under consideration in the present investigation is Isopropyl Alcohol or IPA. IPA is also known as Isopropanol and is a compound with chemical formula  $\text{CH}_3\text{CHOHCH}_3$ .
7. IPA can be produced either using acetone route or propylene route. The applicant has submitted that they are using propylene route for manufacturing IPA. However, it needs to be emphasized herewith that the production of IPA through two different routes, which require usage of different raw materials, does not lead to any difference in the final product. The product is used for the same applications and in the same manner. There is no difference between the characteristics of the final product manufactured using both the technologies.
8. The product produced by the domestic industry is like article to the goods imported from the subject country. The product produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of physical & chemical properties, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Even though there are different manufacturing process/technologies involved for production of the subject goods, the end product has comparable specifications and is used interchangeably. In view of the same, the product manufactured by the domestic industry is considered as like article to the product imported into India.
9. The product under consideration is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under the HS Code 2905 1220. The customs classification is only indicative and not binding on the scope of the product under consideration in the present investigation.

## D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

10. The petition filed by the domestic industry highlighted that Deepak Phenolics Limited was considered ineligible by the applicant due to its imports of the subject goods during the period of investigation. The petitioner, however, believed it was eligible despite also importing goods from a different country. Deepak Phenolics imported \$2.12 million worth of goods from China PR, while the petitioner imported \$7.14 million from Korea, alleging a deliberate attempt to sway the Authority. The petitioner's consistent imports

from Korea indicate a strategy to avoid China and continue importing from other countries at similar prices. This raises concerns about the eligibility criteria for the domestic industry.

## D.2 Submissions by the domestic industry

11. The submissions made by the domestic industry with regard to scope of the domestic industry and standing are as follows:
- i. Apart from the applicant, there is only one other domestic producer of the subject goods in India, that is, Deepak Phenolics Limited (“DPL”).
  - ii. DPL has imported the subject goods from the subject country during the period of investigation. Thus, the producer should be considered ineligible for the purpose of determining standing.
  - iii. The applicant has not imported the product under consideration from the subject country during the period of investigation and is not related to any importer in India or any exporter from the subject country.
  - iv. The imports were made from non-subject countries, primarily South Korea. As per Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules, an applicant may be considered ineligible to constitute domestic industry in case it is an importer of dumped article. Since dumping investigation is only applicable for the imports from the subject country, imports made by the petitioner from other countries do not bar the petitioner from constituting domestic industry.

Particulars	Unit	2022-23
Imports made by petitioner	MT	***
Production in India	MT	***
Demand in India	MT	***
Imports in relation to production	%	***
Imports in relation to demand	%	***

- v. The quantity of imports stated by other interested parties during the oral hearing was overstated. The imports are negligible compared to production and consumption in India, as shown in the table above.
- vi. In case, DPL is considered ineligible, the applicant accounts for 100% production of like article in India.
- vii. In case, DPL is considered eligible, the applicant still accounts for a major proportion of domestic production in India and thus, satisfies the requirement as per Rule 2(b) and Rule 5 of the Anti-Dumping Rules.

## D.3 Examination by the Authority

12. Rule 2(b) of the Rules defines domestic industry as follows:

*“(b) 'domestic industry' means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers.”*

13. The application for initiation of the present investigation has been filed by Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Limited. The applicant has submitted that there is only one other producer of the subject goods in India, that is Deepak Phenolics Limited. DPL has submitted a letter supporting imposition of anti-dumping duty on imports of the product under consideration from the subject country. It is noted that the applicant has not imported the product under consideration and is not related to any importer in India or any exporter from the subject country.
14. The applicant has submitted that Deepak Phenolics Limited (DPL) has imported the product under consideration from the subject country during the period of investigation. This assertion is supported by DPL's statement and the same is also verified through DG Systems data. Since, DPL has imported the PUC from the subject country, the Authority deems DPL ineligible for the purpose of determining standing.

Accordingly, the Authority holds that for the purpose of this investigation, the applicant accounts for 100% of the domestic production in India and satisfies the standing requirement of Rule 2(b) read with Rule 5(3) of the Rules.

15. In response to the interested party's claim that the petitioners' consistent imports from Korea suggest a strategy to circumvent China and continue importing at similar prices, raises concerns about the eligibility criteria for the domestic industry, the Authority notes that the term "themselves importers thereof" in Rule 2(b) of the AD Rules 1995 refers to domestic producers who are involved in importing the alleged dumped article. The word "thereof" explicitly refers to the alleged dumped articles. Further, "alleged dumped article" in the said rule pertains to goods from the country accused of dumping i.e. subject country, which is China in the present investigation. Since the applicant has not imported the subject goods from China, there is no question regarding the eligibility of the applicant as domestic industry for this investigation. Arguendo, the Authority verified that Deepak Fertilizers imported \*\*\* MT of subject goods from Korea, amounting to \$\*\*\* million. These imports represent \*\*\*% of the total imports and \*\*\*% of the total demand during the period of investigation. This data indicates that the volume and value of imports from Korea RP are relatively minor in the context of the overall market, undermining the claim that the exclusion was intended to influence the investigation's outcome.
16. The Authority further notes that even in case the production of DPL is taken into consideration for the purpose of determining standing, the applicant solely accounts for major proportion of domestic production in India and thus, satisfies the requirement of Rule 2(b) read with Rule 5(3) of the Rules.

## **E. CONFIDENTIALITY**

### **E.1 Submission by the other interested parties**

17. No submissions have been made by the other interested parties with regard to confidentiality.

### **E.2 Submissions made by the domestic industry**

18. The submissions made by the domestic industry with regard to confidentiality are as follows:
- i. Zhuhai Long Success Chemical Industry Co. has claimed excessive confidentiality as it has claimed the list of products produced / sold, shareholding, production process, number of employees and details of related parties confidential.
  - ii. Fox Chem Pte Limited and SK Chemical Trading (HK) Limited have claimed excessive confidentiality as they have not disclosed the related parties involved in production and sales of the subject goods as well as shareholders of the company.

### **E.3 Examination by the Authority**

19. Rule 7 of the Anti-Dumping Rules provides as follows:

*"7. Confidential Information:*

*(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*

*(2) The designated authority may require the interested parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible.*

*(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."*

20. The information provided by all the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, the parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis, which was duly circulated to all the interested parties.

## **F. MISCELLANEOUS ISSUES**

### **F.1 Submission by the other interested parties**

21. The producer/exporter argues that the domestic industry has failed to prove that China is setting benchmark prices, especially when imports from various countries undercut prices. There are no clear criteria to determine which country sets benchmarks in anti-dumping investigations, and price data shows significant

fluctuations from China PR, Taiwan, Korea RP, USA, and Netherlands. Chinese exporters do not consistently set lower benchmarks compared to other countries. Pricing strategies are influenced by market conditions, currency fluctuations, and global trade dynamics. It is crucial to evaluate imports from all major sourcing countries to effectively address injury to the domestic industry. The Authority is urged to review and apply trade measures consistently across all involved countries, rather than focusing solely on China PR.

22. The investigation against China PR was initiated based on the petitioner's application, primarily focusing on Chinese exports, citing price undercutting and material injury to the domestic industry. However, import prices from China were similar to those from Taiwan, Korea, USA, and the Netherlands, collectively constituting 99% of total imports. The producer/exporter argues that the investigation should have been initiated against all countries whose import prices closely resemble those of China, especially those meeting the threshold of 3% import volume. Annexure II of the Anti-Dumping Rules mandates a cumulative assessment of the impact of imports from multiple countries when the margin of dumping exceeds 2% of the export price, and the volume of imports from each country is at least 3% of the total imports, or collectively these countries account for more than 7% of total imports.
23. It has also been argued that focusing on one country, like China in this case, without considering others could be seen as arbitrary and discriminatory. It may not effectively address the issue of price undercutting and harm to the domestic industry from various sources. Therefore, the Authority is urged to evaluate all exporting countries' behavior fairly.
24. Imports from Taiwan, Korea, USA, and the Netherlands individually exceed the 3% threshold, making up 99% of total imports, including from China. The current investigation may violate WTO rules by not including all relevant countries. A broader investigation is needed to comply with anti-dumping laws and ensure fairness.
25. It has been submitted that in accordance with Para 11.7.2 of the Manual of Operating Practices for Trade Remedy Investigations, a cumulative assessment is warranted in the current investigation. The criteria stipulate that such assessment must be undertaken when imports from individual countries exceed 3% of the import volume of the like product, and collectively surpass 7%. These conditions are satisfied in the present investigation. Furthermore, it is noted that the margin of dumping from all other countries is expected to fall within a similar range as that of China PR, given the similarity in their CIF prices. Therefore, in the interest of ensuring a thorough and legally sound investigation, it is recommended that the Authority proceed with a cumulative assessment in the present investigation.
26. The producer/exporter also argues that focusing the investigation only against China will not fully mitigate the injury to the domestic industry. Prices from countries like Taiwan, Korea RP, USA, and Netherlands have been competitive or lower than China in the past. To effectively combat the injury caused by unfairly priced imports, a thorough investigation involving all relevant countries is necessary. This comprehensive approach ensures a fair and uniform application of any anti-dumping measures. Failure to include all countries could result in ongoing unfair competition and insufficient protection for the domestic industry.

## F.2 Submissions made by the domestic industry

27. The investigation targets anti-dumping duties on imports from China, the primary price setter in the Indian market. Despite significant imports from countries like South Korea, Taiwan, the USA, and the Netherlands, only China's imports have surged during the investigation period, while imports from other major countries, except the USA, have declined.

Countries	2021-22	2022-23	Change	
			Volume	%
China	38,364	76,040	37,676	98%
Taiwan	23,152	13,890	-9,262	-40%
Korea	36,759	14,860	-21,899	-60%
USA	5,691	8,763	3,072	54%
Netherlands	7,457	4,498	-2,959	-40%
<b>Total for Other countries</b>	<b>8,188</b>	<b>1,478</b>	<b>-6,710</b>	<b>-82%</b>
<b>Total for these countries</b>	<b>81,247</b>	<b>43,489</b>	<b>-37,758</b>	

28. Imports from the USA are relatively small, at 8,763 MT, constituting only 6% of India's total imports and 4% of its demand. In contrast, while China increased its imports by 37,676 MT, other countries collectively lost 37,758 MT, indicating that Chinese producers replaced suppliers from other countries. Monthly data reveals

that USA imports occurred only in the third quarter of the investigation period. Additionally, China's average import price was lower than that of all non-subject countries, leading to a complete substitution of imports from other nations by the Chinese products.

29. The applicant further submitted that the Authority must assess whether dumped imports from China are a major factor in causing injury. It is not necessary for dumped imports to be the sole or principal cause of injury; they need only be one of the contributing factors. In the case of European Communities – Anti-dumping duties on Malleable Cast Iron Tube or Pipe Fittings from Brazil [DS 219], the Panel determined that even if imports from other countries have contributed to material injury, they do not negate the causal link between dumping and the injury.

*7.367 In its determination, the European Communities identified certain factors, other than dumped imports, that were potentially causing injury to the domestic industry including imports from third countries not subject to the investigation; decline in consumption and substitution. With respect to each of these factors individually, the European Communities conducted a separate examination and found either that it “is not such as to have contributed in any significant way to the material injury suffered by the Community industry” (decline in consumption); that it made “no significant contribution” (export performance) or that “no significant influence” could have resulted (own imports of the product concerned), that it cannot have significantly contributed to injury (substitution), or (in the case of imports from the countries not subject to the investigation) “even if imports from other third countries may have contributed to the material injury suffered by the Community industry, it is hereby confirmed that they are not such to have broken the causal link between the dumping and the injury found”). **The European Communities concluded that any other factors that may have contributed to the injury to the domestic industry were “not such as to have broken the causal link” between dumped imports and injury.***

*7.368 These aspects of the EC determination indicate to us that the European Communities analysed individually the causal factors concerned and identified the individual effects of each of these causal factors. With respect to each of the factors, the European Communities concluded that the extent of the contribution to injury was not significant, or, in one case, extrapolated that, even if the effect were significant, it would not be such as to “break the causal link” between dumped imports and material injury. The European Communities' overall conclusion was that none of these factors had an effect that was such to have broken the causal link between dumped imports and material injury.*

*7.369 We are certainly aware of the theoretical possibility that a causation methodology which separates and distinguishes between individual injury factors may not accommodate the possibility that multiple “insignificant factors” might collectively constitute a significant cause of injury such as to sever the link between dumped imports and injury. However, the EC methodology -- which we understand to separate and distinguish between the effects of each of these causal factors and the dumped imports including through an examination as to whether the extent of the effects of each causal factor are such that it is necessary to separate and distinguish its effects -- does not leave the effects of those factors entirely lumped together and indistinguishable.*

30. Para 7.250 of 7.253 of United States – Anti-dumping measures on certain *Hot-Rolled Steel Products from Japan [DS 184]* also states that Article 3.5 of the AD Agreement mandates that authorities demonstrate a causal link between dumped imports and injury to the domestic industry. This involves a thorough review of all relevant evidence and consideration of other factors causing harm. Authorities must ensure that injuries from these other factors are not wrongly attributed to dumped imports. The requirement emphasizes avoiding simplistic conclusions and confirms that injuries from other factors must not disrupt the causal link between dumped imports and material injury. The decision in *United States – Atlantic Salmon* remains relevant, affirming that the principle of non-attribution of injuries to dumped imports is unchanged despite Japan's claims of substantive text changes.
31. Anti-dumping duties can be imposed on imports from a single country if those imports are causing injury to the domestic industry. The key legal requirement is that dumped imports must be one of the causes of injury. The European Union has imposed such duties on imports from individual countries despite significant imports from other nations. For example:
- **Calcium Silicon from China:** Although imports from Brazil and non-subject countries were significant, the European Commission focused on China, citing its higher volume and greater impact on injury compared to Brazil and other sources.
  - **Birch Plywood from Russia:** Despite imports from Belarus and Ukraine being present, the EU only targeted Russia due to the limited presence of the other imports in the market.
32. The practice confirms that anti-dumping duties can address injury from a single country without needing to consider imports from all other countries, even if those imports are significant.

33. Further, the law does not outline criteria for selecting subject countries for anti-dumping investigations. It specifies that investigations must be terminated if imports from a subject country are below 3% individually or 7% cumulatively. The Rules address termination conditions rather than selection criteria. Annexure II of the Rules on cumulative assessment applies only when more than one country is simultaneously investigated. Since the current case involves only one country, this rule does not apply. Furthermore, there is no evidence of dumping from other countries, which is necessary for including them in the investigation.

### F.3 Examination by the Authority

34. The arguments given by all the interested parties with respect to the initiation being bad in law were analysed within the framework of applicable rules in force. In this regard, the Rule 14 of the AD Rules, 1995 states the circumstances under which the investigation shall be terminated. Rule 14(d) requires that the investigation must be terminated if imports from a specific country account for less than three percent of the total imports of the like product unless countries individually contributing less than three percent of imports collectively account for more than seven percent of the total import volume of the like product.
35. The Authority in this reference, observes that there is no prevailing specific law prohibiting the initiation of an investigation against one country, even if imports from other countries are substantial. Therefore, the current investigation does not contravene any legal standards simply because it focuses solely on Chinese imports to assess injury.
36. In light of allegations from interested parties that imports from other countries Taiwan, Korea, USA and Netherlands were significant and the domestic industry's contention that China was setting market prices, the Authority meticulously examined whether Chinese prices were lower or higher compared to imports from Taiwan, Korea, USA, and the Netherlands. Notably, import volumes from these countries exceeded *de minimis* limits during the period of investigation (POI). However, in this instance, the Authority has observed specific circumstances, which are addressed in the subsequent paragraphs.
37. The Authority conducted a comprehensive comparison of import prices, analyzing data on a monthly basis to account for significant price fluctuations over time. To ensure a robust assessment, a weighted average price difference was calculated between China and each of the other major suppliers, taking into consideration the respective import volumes from China.

### Month-wise Price Trend of China and Other Countries

Monthly Price Analysis										
Month	China		Taiwan		Korea RP		USA		Netherlands	
	Quantity	Rs./MT	Quantity	Rs./MT	Quantity	Rs./MT	Quantity	Rs./MT	Quantity	Rs./MT
Apr-22	9,547	81,774	173	97,951	1,399	86,231	-	-	12	-
May-22	6,488	89,025	1,930	88,603	-	-	-	-	12	-
Jun-22	8,097	88,956	1,697	95,450	1,998	88,378	-	-	1,502	84,859
Jul-22	8,043	89,883	1,003	88,137	-	-	-	-	12	-
Aug-22	-	-	13	1,55,424	-	-	-	-	-	-
Sep-22	7,463	77,139	-	-	2,969	84,073	-	-	-	-
Oct-22	8,322	77,162	1,785	77,085	1,940	78,930	-	-	1,062	85,914
Nov-22	4,905	77,702	1,016	79,163	-	-	1,504	82,877	12	-
Dec-22	7,607	78,655	2,662	74,524	985	85,012	3,960	79,735	1,539	84,294
Jan-23	2,953	77,757	1,039	74,251	115	1,06,451	19	-	6	-
Feb-23	4,904	76,232	742	77,500	112	1,00,995	321	76,709	12	-
Mar-23	4,094	79,136	1,805	77,838	5,091	77,483	2,960	74,883	6	-
<b>Total</b>	<b>72,423</b>	<b>81,828</b>	<b>13,864</b>	<b>81,635</b>	<b>14,610</b>	<b>82,259</b>	<b>8,763</b>	<b>80,215</b>	<b>4,177</b>	<b>93,156</b>

**Monthly and weighted Average Price difference between China and Other Countries (Taiwan, Korea, USA and Netherlands )**

(Rs./MT)

Month	Quantity Exported by China (MT)	Taiwan	Korea	USA	Netherland
Apr-22	9,547	16,177	4,457	-	-
May-22	6,488	-422	-	-	-
Jun-22	8,097	6,494	-578	-	-4,096
Jul-22	8,043	-1,746	-	-	-
Aug-22	-	-	-	-	-
Sep-22	7,463	-	6,934	-	-
Oct-22	8,322	-76	1,768	-	8,752
Nov-22	4,905	1,461	-	5,176	-
Dec-22	7,607	-4,131	6,357	1,080	5,639
Jan-23	2,953	-3,506	28,694	-	-
Feb-23	4,904	1,268	24,763	478	-
Mar-23	4,094	-1,298	-1,653	-4,253	-
<b>Weighted Average Price Undercut</b>	<b>72,423</b>	<b>2,153</b>	<b>4,862</b>	<b>256</b>	<b>1,140</b>

38. The above analysis revealed that the import prices from China were lower than those from Taiwan, Korea, USA, and the Netherlands in the present POI. Further, it was these low priced Chinese imports which forced the other countries also to reduce their prices. This finding strongly suggests that Chinese import prices exerted downward pressure on the overall market price.
39. Furthermore, despite other countries' attempts to remain competitive by adjusting their prices to match those of Chinese exports, they experienced a decline in import volumes during the POI. It is seen that whereas the Chinese imports increased by approximately 37,000 MT, imports from major exporting countries collectively declined by 31,000 MT. This clearly shows that the low prices of Chinese imports not only undercut the prices of other suppliers but also significantly impacted their volume and market share.

Countries	Volume (MT)				Price (Rs./ Unit)			
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
CHINA P RP	78,685	52,332	35,758	72,423	50,272	92,645	82,240	81,828
TAIWAN	7,676	19,859	22,593	13,864	55,305	86,532	83,789	81,635
KOREA RP	28,823	34,691	34,547	14,610	52,336	89,061	80,955	82,259
U S A	9,862	18,952	5,695	8,763	54,958	81,783	79,344	80,215
NETHERLAND	5,162	5,033	6,440	4,177	53,347	93,117	89,754	93,156

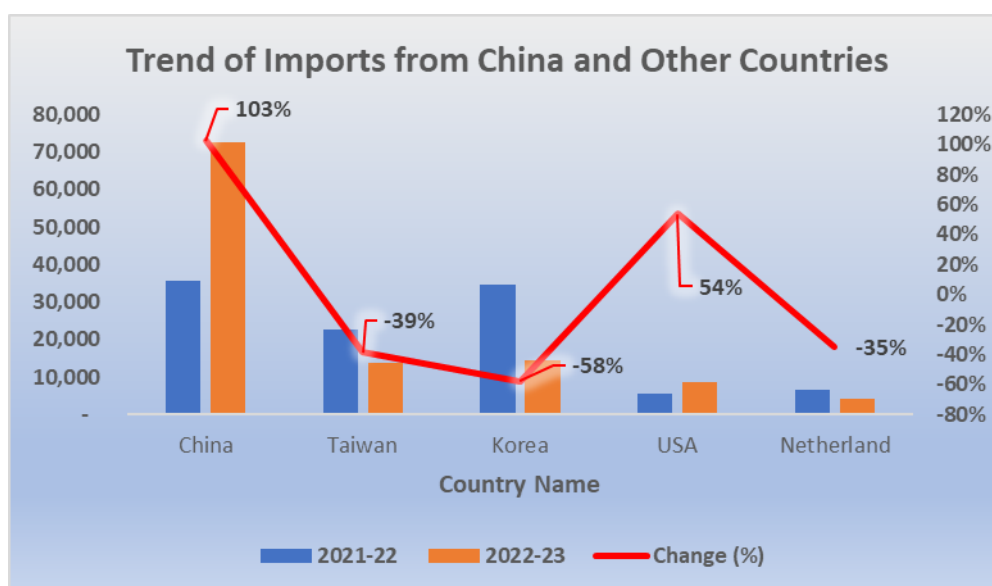
40. The Authority examined the import data from DG Systems and observed there has been significant increase in the imports from China and substantial decline in the imports from other countries, except for those from the USA. The same is depicted in the table given below. As regards imports from USA, it has been noticed that exports by USA were not regular and it happened only at the end of POI between December, 2022 to March 2023. A significant increase of more than 100% in imports from China during the POI and simultaneous decline in the imports from other countries clearly reflects dominance of Chinese exporters/producers

controlling the market. Moreover, the decision not to initiate investigation against other countries does not negate the potential injury inflicted by Chinese imports on the domestic industry.

#### Trend of Imports from China and Other Countries

Import	2021-22	2022-23	Change (%)
China	35,758	72,423	103%
Taiwan	22,593	13,864	-39%
Korea	34,547	14,610	-58%
USA	5,695	8,763	54%
Netherland	6,440	4,177	-35%

41. A graphical representation of trend of imports from China and other countries is also depicted as follow to show the significant increase in the imports from China and decline in imports from other countries especially accounting for more than 3% of total imports in India.



42. The examination of pricing data, market share trends, and the overall impact on the domestic industry establishes that Chinese imports were the primary and predominant cause of the material injury.

#### G. MARKET ECONOMY TREATMENT (MET), NORMAL VALUE, EXPORT PRICE & DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

##### G.1 Submissions by the other interested parties

43. After December 11, 2016, i.e., after expiry of the China's Accession Protocol, India's Basic Anti-Dumping Regulations cannot establish normal value for Chinese exporting producers based on domestic prices and costs. This means that India no longer has a legal basis to calculate normal value in anti-dumping investigations of Chinese products using non-market economy methodology. If India does not comply, China PR may challenge the legislation, as it is inconsistent with India's WTO obligations. The Ministry of Commerce and Industry is obligated to obtain necessary information for calculating dumping margins in accordance with WTO rules.

44. China PR should be granted "market economy status" based on its market economy development, and normal value calculations should following Article 2 of the Anti-Dumping Agreement, using the data filed by the company in its response.

##### G.2 Submissions by the domestic industry

45. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to market economy treatment, normal value, export price and dumping margin:



- i. China PR should be treated as a non-market economy in accordance with Article 15(a)(i) of China's accession protocol, and the normal value should be determined in accordance with Para 7 of Annexure I to the Rules.
- ii. The WTO members only need to use domestic prices or costs in China if producers prove that market economy conditions apply to their industry. Since the producers have not demonstrated this, the Designated Authority is not required to use China's domestic prices or costs to determine normal value. This approach is consistent with the Designated Authority's treatment of China as a non-market economy in recent investigations, including the sunset review of anti-dumping measures on Electric Insulators from China (Case No. 7/44/2018-DGTR).
- iii. The normal value has been determined for the subject country on the basis of FOB price of exports from Korea RP to countries other than India. Such prices are adjusted for port expenses, bank charges and inland freight.
- iv. Alternatively, the applicant has also constructed the normal value based on price payable in India duly adjusted for selling, general and administrative expenses and reasonable profits.
- v. The applicant has determined the export price as per DGCI&S published data. Adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, bank charges and inland freight.
- vi. The dumping margin is positive and significant.

### G.3 Examination by the Authority

46. The Authority had sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject country, advising them to provide the information in the form and manner prescribed by the Authority. Response to exporter's questionnaire has been filed by Zhuhai Long Success Chemical Industry Co., Ltd., Fox Chem Pte Limited and SK Chemical Trading (HK) Limited.

#### G.3.1 Determination of normal value

##### Examination of Market Economy Status

47. The Authority had sent questionnaires to known producers / exporters from the subject country, advising them to provide the information in form and manner prescribed by the Authority. None of the producers have filed response to the supplementary questionnaire for claiming market economy treatment. Accordingly, the normal value for the producers from China PR has been determined as below.

48. Article 15 of the China's Accession Protocol to the WTO provides as follows:

*"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:*

*(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:*

*(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*

*(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*

*(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.*

(c) *The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*

(d) *Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."*

49. The treatment of China PR as a non – market economy does not solely stem from Article 15 (a) (ii) –but also flows from the remaining text of Article 15 i.e., subparagraph (a), as well as the broader rules set forth in Article VI of GATT 199435 and Article 2.2.1.1 of the WTO Anti-Dumping Agreement. As per the current international framework emerging from Article 15 of China's Accession Protocol, read with GATT Article VI and Article 2.2.1.1 of the Anti-Dumping Agreement, there are no restrictions in treating China PR as non-market economy. It is noted that although Article 15 (a)(ii) has expired, Article 2.2.1.1 of the Anti dumping Agreement read with the Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol to the WTO indicate that producers/exporters from China PR may be required to prove that market economy conditions exist in China PR. Further, paragraph 8 of Annexure I to the AD Rules stipulates that any country that has been determined to be or has been treated as a non-market economy country, is presumed to be a non-market economy. Exporters from such country may rebut such a presumption by providing information/evidence stipulated in paragraph 8(3) of Annexure-I to the AD Rules in the form of a response to the supplementary questionnaire issued by the Authority. Therefore, the burden is on the producers/exporters to prove that Market Economy Conditions prevail in the subject country.

50. The Authority has a consistent practice of treating China PR as a Non-Market Economy. It is noted that since the responding producers/exporters from China PR has not filed a response to Market economy treatment/Supplementary questionnaire to dispute the presumption that market economy conditions exist in China PR, the normal value computation is required to be done as per the provisions of paragraph 7 of Annexure I of the Rules, which reads as under:

*"7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."*

51. The normal value for China PR has been determined on the basis of price payable in India, calculated as per cost of production in India, duly adjusted, for selling, general & administrative expenses and reasonable profits. The normal value so determined is indicated in the dumping margin table below.

#### **Determination of Export Price**

52. The followings producers / exporters have filed responses to Exporters' Questionnaire:

- i. Zhuhai Long Success Chemical Industry Co., Ltd.
- ii. Fox Chem Pte Limited
- iii. SK Chemical Trading (HK) Limited

#### **Export price for Zhuhai Long Success Chemical Industry Co., Ltd, Fox Chem Pte Limited and SK Chemical Trading (HK) Limited**

53. Zhuhai Long Success Chemical Industry Co., Ltd. is the producer of the product under consideration and has exported the subject goods to India through unrelated exporters, namely, Fox Chem Pte Limited and SK Chemical Trading (HK) Limited. The Authority notes that the producer has sold \*\*\*MT to unrelated traders. Out of the said sales Fox Chem Pte Limited has exported \*\*\*MT to India and SK Chemical Trading (HK) Limited has exported \*\*\* MT to India. The producer/unrelated exporter has claimed adjustment on account of ocean freight and credit cost.

54. The Authority has undertaken desk verification and examined the claims made by the respondent. The adjustments claimed by the respondent have been allowed. However, the producer/unrelated exporter did not claim the insurance cost. Therefore, to calculate the CIF price, the Authority has computed the insurance cost as 0.5% of the net invoice value, which is also applied by the applicant to calculate their claimed net export price. The net export price so determined is given below in the dumping margin table.

**For all other producers / exporters from China PR**

55. The export price for all other producers and exporters, that have not participated in the present investigation, has been determined as per facts available after allowing due adjustments for ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses and inland freight. The same has been mentioned in the dumping margin table.

**Dumping Margin**

56. Considering the normal value constructed as provided above, and export price as determined, the dumping margin determined for the subject country is as follows:

S.N.	Name of Producer	Normal Value	Export Price	Dumping Margin	CIF Value	Dumping Margin (% based on CIF)	Dumping Margin %
		(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)	(MT)	(Range)
<b>China PR</b>							
1	Zhuhai Long Success Chemical Industry Co., Ltd,	***	***	***	***	***	20-30
2	Non-cooperative / residual exporters	***	***	***	***	***	40-50

**H. INJURY ASSESSMENT AND CAUSAL LINK**

**H.1 Submissions by other interested parties**

57. The domestic industry's injury is attributed to factors other than imports from China PR. If any injury occurs, the Director General must examine known factors causing injury to the domestic industry.
58. The Appellate Body in US – Hot-Rolled Steel ruled that investigating authorities must assess the injury caused by other known factors and separate the injurious effects of dumped imports from those of other factors. This requires a satisfactory explanation of the nature and extent of the injurious effects of the other factors, as distinguished from the injurious effects of the dumped imports. It is crucial that non-attributive factors are analyzed in detail by the Director General before rejecting other factors causing injury to the domestic market. To determine the injury caused to the petitioner, three issues must be considered: analyzing the effect of other factors, determining the extent of their effect on the petitioner, and making a detailed analysis of the impact of any factor.
59. The Directorate General of Trade Remedies (DGTR) is criticized for its lesser duty rule and non-injurious price calculation, which is deemed highly inflated and not based on real situations. The law requires reasonable return to arrive at the non-injurious price, and the DGTR should adopt the return on capital employed (ROCE) earned by the industry when there was no allegation of dumping as a reasonable profit margin.
60. The 22% ROCE is incorrect as it provides more than 22% return on net worth portion of capital employed, which is not acceptable during a global recession. The DGTR's 22% ROCE is also deemed unreasonable, as it was introduced by the Government of India in the Drugs (Prices Control) Order, 1987, specifically designed for fixing prices of bulk drugs. The 22% ROCE cannot be considered reasonable after 37 years, as interest rates and corporate tax have come down. The DGTR is giving undue protection to the domestic industry. Further, in the case of Bridgestone Tyre Manufacturing & Ors. v. Designated Authority, the Ld. CESTAT observed that the price of 22% ROCE adopted by the Authority is not correct.

## H.2 Submissions by the domestic industry

61. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to injury and causal link:
- i. The imports have increased in India in absolute terms and in relation to production and consumption in India.
  - ii. The imports have increased at a rate much higher than the increase in demand. The subject imports have taken up the market share of the Indian industry as well as imports from other countries.
  - iii. The subject imports are forcing exporters from other countries to reduce the prices of exports to India.
  - iv. The imports are significantly undercutting and causing a strain on the prices of the domestic industry.
  - v. Price undercutting was highest during the period of investigation.
  - vi. The capacity utilization, production, domestic sales and market share of the domestic industry has declined, despite demand-supply gap in the country.
  - vii. The domestic industry has suffered financial losses, cash losses and recorded a negative return on investment during the period of investigation.
  - viii. The interest coverage ratio of the domestic industry has declined during the period of investigation as compared to the injury period.
  - ix. The inventories of the domestic industry have increased by \*\*\*% in the period of investigation as compared to the previous year.
  - x. The domestic sales of the industry have significantly declined during the period of investigation as compared to 2020-21 and 2021-22 despite a significant increase in the demand.
  - xi. The domestic industry has suffered material injury and there is a threat of further material injury to the domestic industry.
  - xii. There is threat of material injury as the subject imports have increased 1.9 times during the period of investigation, there are surplus capacities in China and the subject imports are priced below the selling price and cost of sales of the domestic industry.
  - xiii. The injury to the domestic industry is due to dumping of imports from China PR.
62. The applicant further submits that it is a multi-product company, manufactures various products at a single location using different plants. Utilities such as power and steam are internally generated and consumed, originating from a centralized plant but allocated individually to each product's plant. Detailed records are maintained to track utility usage by each plant. Due to IPA's specific manufacturing chemistry, it consumes more utilities compared to other products. Therefore, the actual utilities consumed in IPA production should be considered when determining the non-injurious price for the domestic industry.
63. The applicant utilizes Propylene for IPA production, sourced from different suppliers at varying purity levels, which affects consumption rates and prices. Higher purity reduces consumption but increases costs, while lower purity increases consumption and reduces prices. The Authority should standardize raw material usage based on optimal purity and consider pricing from the period of investigation to avoid distorting calculations of the non-injurious price. Alternatively, the Authority may adjust data to calculate consumption based on the purity used during the injury period and standardize raw material usage accordingly. Pricing adjustments may also be necessary. The petitioner urges fair evaluation without unfairly criticizing their efficient input use.
64. The arguments of other interested parties should be dismissed because the Tribunal consistently maintains that a return of 22% is standard for determining the non-injurious price, unless evidence is presented to justify a different rate. In the case of Bridge Stone Tyre Manufacturing Vs. Designated Authority, evidence showing lower returns globally was submitted. However, after this decision, Tribunal has upheld the 22% return unless compelling evidence proves otherwise. For instance, in Tangshan Sanyou Group Hong Kong International Trade Co. Ltd. Vs. Union of India [2017 (349) E.L.T. 667 (Tri. - Del.)], the Tribunal upheld this practice due to the absence of evidence challenging the reasonableness of the 22% return set by the Designated Authority. It may be considered that the other interested parties have not provided any evidence of the fact that 22% should not be considered.

## H.3 Examination by the Authority

65. The Authority consistently applies a 22% Rate of Capital Employed (ROCE) as standard practice in all anti-dumping investigations. The observations of the Ld. CESTAT in the Bridgestone case were specific to the use of 22% ROCE in determining price underselling, not its appropriateness in computing the Non-Injurious Price

(NIP). Moreover, the Bridgestone decision predates the introduction of Annexure-III to the AD Rules, rendering reliance on it by other interested parties is unjustified. In the subsequent Merino Panel Products case, the Ld. CESTAT upheld DGTR's practice of applying a 22% ROCE.

66. The non-injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the verified information and data relating to the cost of production for the period of investigation in respect of the domestic industry. Detailed analysis / examination and reconciliation of the financial and cost records maintained by the companies, wherever applicable, were carried out for this purpose.
67. The request of the domestic industry to standardize raw material usage based on purity and consider pricing from the period of investigation to avoid distorting calculations of the non-injurious price has been examined. It has been noted that the domestic industry procures raw material (refinery grade propylene) from two sources namely BPCL Mahul and BPCL Kochi. The contention of the domestic industry that the raw material procured from the BPCL Kochi has higher degree of purity, which requires less consumption quantity whereas the raw material procured from BPCL Mahul has lower degree of purity requiring higher amount of consumption quantity. However, the data submitted by the applicant not reflect the same. It has been noted that during 2019-20 and 2020-2021 the consumption norm was \*\*\* and \*\*\* respectively where the producer utilised the raw material from both sources with almost in similar range in both years. Hence, the plea of the domestic industry to standardize the consumption norm based on purity is not found to be tenable and could not be considered for finalizing the NIP.
68. The Authority has taken note of various submissions made by the domestic industry with regard to the injury assessment and causal link and has examined the same considering the facts available on record and applicable laws.

### H.3.1 Volume Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry

#### a. Assessment of demand/apparent consumption

69. For the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India has been defined as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	89	107	72
Sales of other domestic producer	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	-	100	142	270
Imports from subject country	MT	78,685	52,332	35,758	72,423
Imports from other countries	MT	58,182	1,07,539	79,176	42,662
Total Demand/Consumption	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	120	108	113

70. Based on the above, the Authority notes that the demand for the product under consideration has increased in 2020-21 as compared to 2019-20. The demand declined in 2021-22 as compared to the previous year and increased again thereafter during the period of investigation.

#### b. Import volumes from the subject country

71. With regard to the volume of the imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports from the subject country, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The same is analyzed in the table below.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
<b>Production</b>					
Domestic Industry	MT	***	***	***	***
Other Indian Producer	MT	***	***	***	***
<b>Total Production</b>	MT	***	***	***	***

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Indexed	Trend	100	133	164	187
<b>Total Demand/Consumption</b>	<b>MT</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
Indexed	Trend	100	120	108	113
Imports from subject country	MT	78,685	52,332	35,758	72,423
Imports from other countries	MT	58,182	1,07,539	79,176	42,662
<b>Total Imports</b>	<b>MT</b>	<b>1,36,867</b>	<b>1,59,870</b>	<b>1,14,934</b>	<b>1,15,084</b>
<b>Subject imports in relation to</b>					
Production	%	***	***	***	***
Indexed	Trend	100	50	28	49
Consumption	%	***	***	***	***
Indexed	Trend	100	55	42	82
Total Imports	%	57%	33%	31%	63%

72. Based on the above, the Authority notes that:

- i. The volume of imports from the subject country declined in 2020-21 and 2021-22 as compared to immediate previous year but increased thereafter during the period of investigation. The imports in 2019-20 were high due to which the domestic industry had filed an application for imposition of safeguard measures in the form of quantitative restrictions.
- ii. Imports in relation to consumption have declined in 2020-21 and 2021-22 as compared to the previous years but increased thereafter during the period of investigation.
- iii. Imports in relation to production has declined in 2020-21 and 2021-22 as compared to the previous year but increased thereafter during the period of investigation.
- iv. Imports in relation to total imports declined in 2020-21 as compared to the previous year and remained stable in 2021-22 as compared to 2020-21 but increased thereafter. Subject imports in relation to total imports was the highest during the period of investigation.
- v. While the demand for the subject goods has increased by only \*\*\*% in the period of investigation as compared to the previous year but the imports from the subject country have increased by \*\*\*% and the imports from non-subject countries decreased by \*\*\*%. The subject imports have not only captured the increase in demand in India but also the existing demand in India.

### H.3.2 Price Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry

73. With regard to the effect of the dumped imports on prices of the domestic industry, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject country has been examined with reference to price undercutting, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with the landed price of imports of the subject goods from the subject country.

#### a. Price Undercutting

74. For the purpose of price undercutting analysis, the selling price of the domestic industry has been compared with the landed price of imports from the subject country. Accordingly, the undercutting effects of the dumped imports from the subject country is as follows:

Particulars	Unit	POI
Landed Price	₹/MT	81,828
Net Sales Realization	₹/MT	***
Price undercutting	₹/MT	***
Price undercutting	%	***
Price undercutting	Range %	20-30

75. The Authority notes that the subject imports are undercutting the prices of the domestic industry and the price undercutting is positive and significant. During the onsite verification, the domestic industry reported that despite the low import price, the domestic industry was able to maintain a little higher price due to its ability to provide a crucial, uninterrupted supply of the subject goods which is essential for its customers in pharmaceutical and chemical industry. Furthermore, the domestic industry's higher selling price led to a marked increase in imports and a consequent decline in domestic sales. This situation resulted in a significant buildup of inventory, followed by reductions in production and capacity utilization. Consequently, the drop in import prices, combined with rising costs, inflicted injury to the domestic industry during the POI.

**b. Price Suppression and Depression**

76. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, are compared as below:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	168	156	165
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	131	142
Landed Price	₹/MT	50,272	92,645	82,240	81,828
Trend	Indexed	100	184	164	163

77. The Authority determines that:

- The imports from the subject country were priced below the cost of sales of the domestic industry during the years 2019-20, 2021-22 and the period of investigation.
- While the cost of sales of the domestic industry has increased during the period of investigation as compared to 2020-21, the landed price has declined during the same period.
- Compared to the previous year, the selling prices of the domestic industry have increased by a smaller margin than the rise in their cost of sales. Meanwhile, the landed prices of the subject imports have decreased during this period. Consequently, the subject imports have suppressed and depressed the prices of the domestic industry.

**H.3.3 Economic Parameters of the Domestic Industry**

78. Annexure II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed hereinbelow.

**a) Production, capacity, sales and capacity utilization**

79. The capacity, production, sales and capacity utilization of the domestic industry over the injury period is given in the following table: -

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	100
Production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	91	108	80
Capacity utilization	%	***	***	***	***

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Trend	Indexed	100	91	108	80
Domestic sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	89	107	72

80. Based on above, the Authority notes the following:

- i. The capacity of the domestic industry has remained the same throughout the injury period.
- ii. The production of the domestic industry has declined by 20% over the injury period and by \*\*\*% in the period of investigation as compared to the previous year.
- iii. The domestic sales of the domestic industry have declined by \*\*\*% over the injury period and by \*\*\*% in the period of investigation as compared to the previous year. The domestic sales of the domestic industry have declined even though the demand has increased in India and the domestic industry has been selling at losses.
- iv. The capacity utilization of the domestic industry has declined by \*\*\*% during the period of investigation as compared to the previous year. The domestic industry was operating at the lowest capacity utilization during the period of investigation as compared to the injury period.

**b) Market share**

81. The market share of the domestic industry and imports of the product into India is shown in the table below.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Subject imports	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	55	42	82
Other imports	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	153	126	65
Domestic industry	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	74	99	64
Other domestic producer	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	-	100	159	289
Total	%	100%	100%	100%	100%

82. Based on above, the Authority notes the following:

- i. The market share of the domestic industry has reduced as compared to the base year as well as the previous year.
- ii. The market share of the subject imports declined in 2020-21 due to commencement of production by the other domestic producer. However, the market share of the subject imports increased again in the period of investigation as compared to the previous year.
- iii. While the demand has increased by 4% in India during the period of investigation as compared to the previous year, the market share of the subject imports have increased by 93% during the same period. Thus, the subject imports captured the growth in demand as well as the existing demand in India.

**c) Inventories**

83. Inventory position of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Opening Inventory	MT	***	***	***	***
Closing Inventory	MT	***	***	***	***
Average Inventory	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	60	52	170



84. Based on the table above, the Authority notes that the inventories of the domestic industry have increased multifold over the injury period. Even though the domestic industry has sold the subject goods at losses, the inventories have increased significantly.

**d) Profitability, cash profits and return on capital employed**

85. Profitability, return on capital employed and cash profits of the domestic industry over the injury period is given in the table below: -

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	131	142
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	168	156	165
Profit/(Loss)	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100	202	-4	-26
Total Profits/(Loss)	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100	181	-5	-17
Cash Profits	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100	313	27	-11
PBIT	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100	381	17	-20
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100	277	20	-16

86. Based on the above table, the Authority notes the following:

- In the year-2019-20, the imports into India increased which caused serious injury to the domestic industry. The domestic industry had filed an application for imposition of safeguard measures during this period.
- While the domestic industry has earned profits during 2020-21, it has incurred losses in 2021-22. Further, the losses have increased during the period of investigation as compared to the previous year.
- The domestic industry has incurred cash losses during the period of investigation.
- The return on capital employed of the domestic industry has declined since 2020-21. The domestic industry has recorded a negative return on capital employed during the period of investigation.

**e) Employment, productivity and wages**

87. Employment, productivity and wages of domestic industry over the injury period is given in the table below.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
No. of employees	No.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	94	94
Productivity per employee	MT/No.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	95	114	85
Productivity per day	MT/Days	***	***	***	***
Trend	No.	100	91	108	80
Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	136	125	78

88. Based on the above analysis, the Authority finds that employment in the domestic industry has steadily decreased throughout the injury period, leading to a corresponding decline in total wages paid. Moreover, the productivity of the domestic industry has suffered over the injury period due to reduced production levels.

**f) Growth**

89. The following table shows the growth parameters of the domestic industry.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Capacity	%	-	-	-	-
Production	%	-	***	***	***
Domestic Sales	%	-	***	***	***
Profit/(Loss) per unit	%	-	***	***	***
Cash profits per unit	%	-	***	***	***
Return on capital employed	%	-	***	***	***

90. Based on the above, the Authority notes that:

- i. The production and sales of the domestic industry have declined in 2020-21 but increased in 2021-22. Thereafter, both the parameters declined during the period of investigation.
- ii. The price parameters improved in 2020-21, however, the same declined during 2021-22 and the period of investigation.
- iii. During the year 2020-21, the domestic industry was in profit even the earned the cash profit, however, during the year 2021-22 it incurred losses, which also increased significantly during POI.
- iv. The return on capital employed was also negative during POI which intensified as compared with previous year.

**g) Ability to raise capital investment**

91. The Authority notes that the ability of the domestic industry to raise capital investment has been adversely impacted. This is due to the fact that the domestic industry has incurred losses in the period of investigation and has recorded negative return on capital employed.

**h) Factors affecting domestic prices**

92. The Authority notes that the landed price of subject imports is below the selling price and cost of sales of the domestic industry. Due to this the domestic industry has been forced to sell at prices below its cost of sales which led to losses incurred during the year 2021-22 and POI. Thus, the subject imports have adversely impacted the domestic prices in India.

**i) Magnitude of Injury and Injury Margin**

93. The Authority has determined non-injurious price for the domestic industry on the basis of principles laid down in Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the verified information relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price of the domestic industry has been worked out and it has been compared with the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials, the utilities and the production capacity of the domestic industry over the injury period have been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax 22%) on the average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules.
94. The landed price of the cooperative producers has been determined as per the data furnished by such producers. For all non-cooperative producers, the Authority has determined the landed price based on the facts available.
95. Based on the landed price and the non-injurious price determined as above, the injury margin for the producers/exports is has been determined by the Authority and the same is provided in the table below.



Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
USA	%	***	***	***	***
Taiwan	%	***	***	***	***
Netherlands	%	***	***	***	***
<b>Imports in relation to total imports</b>					
China PR	%	57%	33%	31%	63%
Korea RP	%	21%	22%	30%	13%
USA	%	7%	12%	5%	8%
Taiwan	%	6%	12%	20%	12%
Netherlands	%	4%	3%	6%	4%

98. Based on the above, the Authority notes that:

- i. While the imports from China PR have increased by 103% during the period of investigation as compared to the previous year, the imports from other countries barring the USA have declined.
- ii. While the imports from China PR have increased in relation to production in India during the period of investigation as compared to the previous year, the imports from other countries barring USA have declined.
- iii. The imports from China PR were almost 9 times the imports from USA. Further, imports from USA were only \*\*\*% the demand in India.
- iv. Imports from China PR dominated the total imports into India. The imports from China PR were more than half the total imports into India.
- v. The imports from China PR were approximately 5 times of the imports from Korea RP and even more than that as compared to other countries.

**b) Contraction in demand**

99. The Authority notes that there is no contraction in demand as the demand for the subject goods in India has steadily increased over the injury period. Thus, the domestic industry has not suffered any injury on this account.

**c) Pattern of Consumption**

100. The Authority notes that there is no change in the pattern of consumption of the subject goods which could have caused injury to the domestic industry.

**d) Trade restrictive practices and conditions of competition**

101. The Authority notes that there are no trade restrictive practices or condition of competition which could have caused injury to the domestic industry.

**e) Export Performance**

102. The Authority notes that the domestic industry has exported a small share of its production in the period of investigation. However, the injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of the domestic market. Thus, the injury suffered cannot be attributed to the export performance of the domestic industry.

**f) Development of Technology**

103. There has been no change in technology for production of the subject goods, due to which the domestic industry has suffered injury.

**g) Performance of other products of the company**

104. The Authority has considered the data relating to the performance of the subject goods only. Therefore, the performance of other products being produced and sold by the domestic industry cannot be a possible cause of injury.

**I. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES****I.1 Submissions by the other interested parties**

105. The producer/exporter argues that providing protection to the Indian industry manufacturing the product under consideration would serve the interests of only the petitioner. The imposition of anti-dumping duty on Isopropyl Alcohol (IPA) imported from China PR poses a severe threat to public interest, particularly for downstream industries heavily reliant on IPA. The monopolistic structure, stifling competition and hindering supply chain diversification, could raise prices for consumers across various sectors, undermining economic growth and industrial competitiveness. The public interest strongly favors refraining from imposing anti-dumping duty, and the government is expected to prioritize fair and protective measures. Any form of protection would provide an undue advantage to the domestic industry at the expense of end-users.
106. Basic Chemicals, Cosmetics & Dyes Export Promotion Council (CHEMEXCIL) has submitted the following:
- i. Deepak fertilizer & Deepak Nitrite have capacities of approximately \*\*\* Mt each, i.e. around \*\*\* Mt in total where as total Indian consumption is around \*\*\* MT per anum.
  - ii. IPA is used by all industries, API, paint, dyes etc. It is used like water. During the current year, based on recommendation of domestic manufacturers, country/region wise quantity restriction was imposed on imports.
  - iii. Due to this reason, the prices which were around Rs. 50-70 kg has gone above Rs. 100/- kg. The current price is Rs. 150/- kg & expect to go up further. Imposing anti-dumping duty will further escalate the price. The Authority should check the cost price, process, input solvents etc of the domestic industry before putting anti-dumping duty and analyze why price from China is low and why domestic industry cannot reach to that stage.
  - iv. Due to the abnormal price rise, industry's business /export has gone down, as we cannot compete with other countries & loose the business due to abnormal price of IPA.

**I.2 Submissions made by the domestic industry**

107. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to public interest:
- i. Imposition of anti-dumping duty will not have an adverse impact on the consumers of the product and public at large. Rather, it will ensure fair competition in India and assist in growth of the domestic industry.
  - ii. The domestic industry was forced to shut down operation due to dumping of subject imports into India.
  - iii. The domestic industry argues that during the Covid-19 crisis, Chinese suppliers exploited opportunities by reducing IPA supplies to India while focusing on their domestic market. This led to increased prices globally and in India. Now, with surplus capacities, they seek to re-enter the Indian market, emphasizing on the need to protect domestic manufacturing from unfair dumping practices.
  - iv. Since IPA is used in manufacturing of pharmaceutical products, it is essential to maintain domestic production of the subject goods in India.
  - v. In case of continued dumping, and shut down of domestic manufacturing in India, the users of the product will be completely dependent upon imports.
  - vi. There is no adverse impact on the downstream industry since IPA is not a raw material but only a solvent. Thus, the cost of the downstream industry on account of IPA is minimal.
  - vii. Since the return on capital employed is negative, the domestic industry might have to shutdown its operations in case the situation stays the same.
  - viii. While the applicant has expansion plans, the same are not feasible due to presence of dumped imports into India.
  - ix. In case of shut down of plant by the domestic industry, the demand-supply gap in the country is likely to increase.
  - x. Imposition of anti-dumping duty does not restrict imports into India. In any case, since there was no demand-supply gap in India even though quantitative restrictions were in force, imposition of anti-dumping duty will not lead to a demand-supply gap.
  - xi. There are alternative sources of imports available which are enough to cater to the demand-supply gap in India. Historically, the imports into India from other countries were higher and have reduced only due to dumping from China.

- xii. Imposition of anti-dumping duty will not lead to monopoly in India as there are two producers of the subject goods in India and the product is being imported from various sources other than the subject country.

### I.3 Examination by the Authority

108. The Authority recognizes that the imposition of the anti-dumping duty would remove unfair advantage gained by the dumping practices, prevent the decline of the domestic industry, and help maintain the availability of wider choice to the consumers of the subject goods. The purpose of anti -dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping duty, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping duty would not restrict imports from the subject country in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
109. Imposition of anti-dumping duty does not restrict imports into India but only ensures that the imports are at fair prices. As per the evidence on record, there will be no scarcity of subject goods in India since the demand-supply gap can be addressed through imports from sources other than the subject country, even in case there are no imports from the subject country.

Particulars	Volume (MT)
Capacity of the applicant	***
Capacity of the other domestic producer	***
Average demand in India*	***
Demand-Supply Gap	***
Imports from other sources**	***

\*Based on demand in 2019-20 to 2021-22

\*\*Highest volume of imports from each country during the injury period

110. It is further seen that there is more than one producer in India and ample of imports are made from countries other than the subject country. Thus, imposition of anti-dumping duty on imports from a single country will not lead to a situation of monopoly in India or the shortage of the product in the country.
111. Therefore, the Authority concludes that the imposition of anti-dumping duty will not have any adverse impact on public at large or the downstream industry.

### J. METHODOLOGY FOR DETERMINATION OF NON-INJURIOUS PRICE

112. The non-injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the verified information and data relating to the cost of production for the period of investigation (April 2022 to March 2023) in respect of the domestic industry. Detailed analysis/examination of the financial and cost records maintained by the companies, wherever applicable, was carried out for this purpose. The non-injurious price for the domestic industry has been determined in terms of the principles outlined in Annexure – III to the Rules as briefly described below:
- Raw Material Cost: The best utilization of raw materials by the domestic producer, over the period of investigation and the preceding three years period, at the rates prevailing in the period of investigation was considered.
  - Cost of Utilities: The best utilization of utilities by the domestic producer, over the period of investigation and the preceding three years period, at the rates prevailing in the period of investigation was considered.
  - Production: The best utilization of production capacity over the period of investigation and the preceding three years period was considered.
  - Salary & Wages: Propriety of the expenses grouped under this head and charged to the cost of production was examined. It is ensured that no extraordinary or non- recurring expenses are charged to the cost of production.
  - Depreciation: The reasonableness of the amount of depreciation charged to the cost of production was examined to ensure that no charge has been made for facilities not deployed on the production of the subject goods.

- f. Identification And Allocation/Apportionment of Expenses: The reasonableness and justification of various expenses claimed for the period of investigation have been examined and scrutinized by comparing with the corresponding amounts in the immediately preceding year and admitted for computing the non-injurious price.
- g. Reasonable Return on Capital Employed: A reasonable return (pre-tax) at 22% on average capital employed (that is Average Net Fixed Assets and Average Working Capital) for the product under consideration was allowed for recovery of interest, corporate tax and profit.
- h. Interest: Interest is allowed as an item of cost of sales and after deducting the interest, the balance amount of return has been allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price.
- i. Non-injurious price for the domestic industry: The NIP for the product under consideration is \*\*\* ₹/MT.

## **K. POST DISCLOSURE COMMENTS**

### **K.1 Submissions by the other interested parties**

113. The petitioner's exclusion of Korea RP from the subject countries in this investigation is an attempt to mislead the Authority, raising serious concerns about the investigation's integrity and fairness. Deepak Fertilizer imported \$7.14 million worth of subject goods from Korea during the period of investigation, indicating a significant business relationship with the Korean producers. We believe the petitioner intentionally omitted Korea RP to allow Deepak Fertilizer to continue importing goods under more favorable conditions while potentially influencing the investigation's outcome. The Authority is urged to thoroughly review this issue in its final findings.
114. The producer/exporter argues that the Authority's month-by-month analysis is flawed as it did not consistently analyze injury and dumping margins across the investigation period. Import prices from Taiwan, Korea, USA, and the Netherlands were often lower than those from China during specific months. Therefore, attributing market price reductions solely to low-priced Chinese imports is inaccurate. Imports from other countries also influence price benchmarks, prompting further reductions in Chinese prices. The investigation should have included all countries whose import prices closely match those of China.
115. The producer/exporter asserts that in anti-dumping investigations, international trade laws stress on non-discrimination and fairness. Targeting one country without considering similar practices by others violates these norms. Anti-dumping measures aim to address unfair trade practices causing injury to domestic industries. A comprehensive assessment across all exporting countries is essential to justify any duties imposed, ensuring compliance with global trade agreements. Focusing only on China, while neglecting comparable practices from other countries, may be perceived as arbitrary and ineffective in addressing broader price undercutting and industry injury.

### **K. Submissions made by the domestic industry**

116. The applicant argues that the Authority's proposed conclusion—highlighting increased demand in 2020-21 and a decline in imports during that year—is flawed. They contend that 2019-20 and 2020-21 are unsuitable for injury analysis because 2019-20 saw import surges causing harm to the domestic industry, and 2020-21 was disrupted by the COVID-19 pandemic, which led to abnormal demand and a reduction in imports by Chinese producers. The applicant asserts that only the year 2021-22 should be used for evaluating changes in demand, imports, and injury to the domestic industry. They also emphasize that assessing injury over a four-year period is crucial for a comprehensive analysis, and comparing only the base year to the investigation period would be unobjective. In light of the above, the applicant argues that the economic situation of the domestic industry should be assessed by considering events throughout the injury period, rather than relying solely on an end-point to end-point analysis.
117. The Authority has noted that while it is a standard practice to initiate investigations against all countries with individual import shares over 3% and conduct a cumulative assessment of injury, this was not done in the present case. Previous investigations, such as those into Decor Paper, Vinyl Tiles, Chlorinated Polyvinyl Chloride, Newsprint, Polytetrafluoroethylene, and PVC Paste Resin, have excluded countries with significant imports, suggesting that the practice of including all such countries is not consistently applied.
118. The applicant contends that the return on investment allowed to the domestic industry for determining the non-injurious price is inadequate at 2.41%. Despite depreciation of their plant and machinery, they argue the domestic industry deserves a reasonable profit. Additionally, the 5% profit margin granted by the Authority for calculating the constructed normal value results in significantly lower profits for the domestic industry compared to foreign producers engaged in dumping.

119. Typically, non-cooperating exporters face higher duties globally to discourage non-cooperation. However, in this case, if duties are set comparable to what would be determined based on their export price, it may incentivize future non-cooperation. Therefore, the Authority is urged to impose higher duties on non-cooperating exporters to maintain the incentive for cooperation.

### **K.3 Examination by the Authority**

120. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the interested parties and notes that majority of the comments/submissions are reiterations which have already been suitably examined and adequately addressed in the relevant paras of the final findings. The same are not being repeated in the post-disclosure examination by the Authority for the sake of brevity. The issues raised for the first time in the post-disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below.
121. The assertion of the interested party that the applicant's exclusion of Korea RP from the investigation constitutes an attempt to mislead the Authority is not supported by the data from DG Systems. Upon review, the Authority verified that Deepak Fertilizers imported \*\*\* MT of subject goods from Korea, amounting to \$\*\*\* million. These imports represent \*\*\*% of the total imports and \*\*\*% of the total demand during the period of investigation. This data indicates that the volume and value of imports from Korea RP are relatively minor in the context of the overall market, undermining the claim that the exclusion was intended to influence the investigation's outcome.
122. The interested party argued that the Authority's month-by-month analysis is flawed due to inconsistent examination of injury and dumping margins with respect to this the Authority notes that it has conducted a detailed monthly analysis and calculated a weighted average price difference between Chinese imports and those from Taiwan, Korea, the USA, and Netherlands. This analysis revealed that Chinese imports were lower in price compared to imports from these countries, exerting significant downward pressure on overall market prices.
123. Furthermore, the significant increase in Chinese imports by approximately 37,000 MT during the period of investigation, coupled with a decline in imports from other major suppliers by 31,000 MT, demonstrates the substantial impact of Chinese pricing on the market. The Authority's analysis indicate that the low prices of Chinese imports not only undercut competitors but also led to a decrease in their market share and volumes. Thus, the month-by-month analysis effectively highlights the role of Chinese imports in driving market price reductions and causing material injury to the domestic industry, reinforcing the appropriateness of the Authority's analysis.
124. The applicant argues that the Authority's use of data from 2019-20 and 2020-21 for demand analysis is flawed because 2019-20 had high import levels and 2020-21 was disrupted by COVID-19. However, it's important to look at demand over several years to understand the full picture. Including data from these years helps to see how demand and imports have changed over time and their overall impact on the domestic industry. Relying only on the year 2021-22 might not give a complete view. By considering the full injury period, the Authority provides a clearer and more accurate assessment of how changes in demand and imports have affected the industry.
125. In response to the claim made by the applicant that it is not a standard practice of the Authority to include all the countries having significant imports, the Authority notes that each anti-dumping investigation is carried out with careful consideration of its specific context to address the unique aspects of each case. In the present investigation, despite imports from other countries exceeding 3%, the Authority has observed that Chinese exporters and producers exert substantial control over the market, leading to a decline in imports from other countries. Consequently, it is concluded that focusing solely on China is sufficient to address the injury to the domestic industry. Therefore, the Authority has not initiated the investigation against all other countries with significant imports.
126. With respect to the concerns regarding calculation of return on investment the Authority notes that ROI has been calculated in accordance with the principles outlined in Annexure III of the Anti-Dumping Rules, 1995, and is based on the data submitted by the domestic industry.
127. The Authority notes that the dumping and injury margins calculated for residual exporters in the current anti-dumping investigation is derived from the DG Systems data and the margins calculated for the participating exporter are below the margins calculated for non-participating exporters. Further, these higher margins reflect a necessary and proportional response to the non-cooperation by the non-participating exporters.



## L. CONCLUSIONS

128. Based on the submissions made, substantiated information provided by the interested parties and the facts available before the Authority as recorded and examined in the aforementioned paragraphs and on the basis of determination of dumping and consequent injury to the domestic industry, the Authority concludes the following:

i. **Product under consideration and like article:** The article manufactured by the domestic industry and the subject goods exported from the subject countries are 'like article' to each other in terms of Rule 2 (d) of the AD Rules, 1995.

ii. **Standing of the domestic industry:** The applicant accounts for 100 % of the eligible domestic production. The applicant satisfies the requirements stipulated under Rule 2 (b) of the AD Rules, 1995 and application satisfies the standing requirements under Rule 5(3) of the AD Rules, 1995.

iii. The application contained all information relevant for the purpose of initiation of the anti – dumping investigation and necessary evidence in terms of Rule 5(2) of the AD Rules, 1995 to justify the initiation of the present investigation for determination of dumping and material injury to the domestic industry in terms of Rule 5 (3) of the AD Rules, 1995.

iv. **Dumping:** One producer from China PR namely Zhuhai Long Success Chemical Industry Co., Ltd. participated in the investigation. Based on the information provided by such exporter and the constructed normal value, the dumping margin for exports of Zhuhai Long Success Chemical Industry Co., Ltd was determined to be positive.

v. **Volume effect:** The volume of imports and the dumping margin of the subject good from the subject country were found to be above *de minimis* thresholds as stipulated under para (iii) of Annexure – II to the AD Rules, 1995.

vi. With respect to the volume effect of the dumped imports on the state of the domestic industry, it was found that such imports have increased in absolute as well as relative terms to the production and consumption of the PUC in India. It was further found that the growth in demand was almost entirely subsumed by such dumped imports.

vii. **Price effect:** As regards the price effect of such dumped imports, it was found that price undercutting from the subject country was positive. It was further found that such dumped imports were adversely impacting the prices of the domestic industry.

viii. **Volumetric and financial parameters of the domestic industry:** As regards the effect of such dumped imports on the economic parameters of the domestic industry, the following conclusions were reached:

a. **Production, capacity, capacity utilisation, sales, and market share:** The applicant's capacity has remained constant. However, due to the presence of dumped imports it was not able to fully utilise its capacities. The applicant's production as well as sales declined in the POI as compared to the injury period. There was considerable growth in demand which was largely met by dumped imports.

b. **Cost of sales, selling price, profitability, and return on capital employed:** The applicant's per unit cost of sales has increased over the injury period. The applicant's selling price have been below the cost of sales except for the year 2020-21. The applicant's cash profits, profit before interest and tax, as well as return on capital employed have significantly declined as compared to the previous year.

c. **Inventories:** The applicant's average inventory increased during the POI.

d. **No. of employees, productivity, and wages:** The number of employees has declined over the injury period. The wages to be paid to them also declined in the POI. However, the productivity of the applicant has been affected due to decline in production as a consequence of dumped imports.

e. **Growth:** The applicant's growth in terms of production, domestic sales, profits and return on capital employed were found to be adversely impacted by the dumped imports.

f. **Ability to raise capital investment:** It was found that despite an increase in demand of the subject goods, the applicant's performance had deteriorated which has impacted its ability to raise capital investments.

ix. **Causal link:** It was found that domestic industry has suffered material injury due to the dumped imports and no other known factors were found to be the cause of the injury. There has been an increase in the volume of the dumped imports during the POI due to which the inventories of the domestic industry have piled up. The presence of dumped imports in the Indian market forced the applicant to sell its like article at prices below its

cost of sales, thereby incurred losses and adversely affected the profitability parameters of the domestic industry.

**x. Injury Margin:** Upon comparison of the non – injurious price determined as per Annexure – III to the AD Rules, 1995 and the landed value of subject imports from the subject countries as required under Rule 17 (3) (b) to the AD Rules, the injury margin for producer from China PR, namely Zhuhai Long Success Chemical Industry Co., Ltd, is found to be positive.

**xi. Indian industry issues:** None of the interested parties filed any substantive quantitative data through which the impact of anti – dumping duties could be assessed on the end user. It is noted that users of the PUC would have options if a viable domestic industry exists.

#### M. RECOMMENDATIONS

129. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all the interested parties including Government of China PR and adequate opportunity was given to them to provide information on the aspect of dumping, injury, causal link and impact of measures, if recommended. Having initiated and conducted the investigation in terms of provisions of investigation as laid down under the Anti-dumping Duty Rules, the Authority has reached a conclusion that the duty is required to be imposed on subject goods.
130. Further, having regard to the lesser duty rule as enunciated in Rule 17 (1)(b) of the AD Rules, 1995, the Authority recommends imposition of definitive antidumping duty equal to the lesser of margin of dumping or margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of such revised definitive anti-dumping duties on the import of the subject goods, originating in or exported from China PR as indicated in Col 7 of the duty table below, for a period of five (5) years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government.

**Duty Table**

SN	HS Code	Description of goods	Country of origin	Country of Export	Producer	Duty (\$/MT)
1	2	3	4	5	6	7
1.	29051220#	Isopropyl Alcohol	China PR	China PR	Zhuhai Long Success Chemical Industry Co., Ltd.	82
2.	-do-	Isopropyl Alcohol	China PR	Any country other than China PR	Any Producer	217
3.	-do-	Isopropyl Alcohol	Any country other than China PR	China PR	Any Producer	217

*# The customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration.*

131. An appeal against the order of the Designated Authority arising out of this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975.

ANANT SWARUP, Designated Authority